राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 11, अंक- 82 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, शुक्रवार ,24 सितम्बर 2021, मूल्य रु. 1.50

अमेरिका में पीएम मोदी ने की 5 ग्लोबल सीईओ से मुलाकात, कंपनियों ने निवेश में दिखाई रुचि

वाशिंगटन, एजेंसी। पीएम मोदी ने मौजूदा समय में अमेरिका दौरे पर है। गुरुवार को पहले दिन पीएम मोदी की पांच कंपनियों के ग्लोबल सीईओ से मुलाकात की। गुरुवार को पीएम मोदी से अमेरिकी कंपनी क्वालकाम के सीईओ क्रिस्टानियो आर एमान, फर्स्ट सोलर के मार्क विडमर, एडोब के शांतनु नारायण, जनरल एटामिक्स के विवेक लाल और ब्लैकस्टोन के स्टीफन ए श्वार्जमैन मिले। बैठक के बाद क्रिस्टियानो आर अमोन कहा कि यह एक शानदार बैठक थी। हमें भारत के साथ साझेदारी पर बहुत गर्व है। हमने 5 जी और इसमें गति के बारे में बात की। हमने न केवल भारत में बल्कि प्रौद्योगिकी के निर्यात के रूप में उद्योग को आगे बढ़ाने के एक अविश्वसनीय अवसर के बारे में बात की।

मुलकात के बाद एडोब के सीईओ शांतनु नारायण ने कहा कि हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी संपत्ति लोग हैं। शिक्षा को प्रोत्साहित करने के संबंध में जो कुछ भी होता है, डिजिटल साक्षरता होने से एडोब को मदद मिलती है। हम शिक्षा में अधिक जोर और रुचि के बहुत समर्थक हैं।

फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क आर विडमार ने कहा कि स्पष्ट रूप से उनके नेतृत्व के साथ और उन्होंने औद्योगिक नीति के साथ-साथ व्यापार नीति में एक मजबूत संतुलन बनाने के लिए क्या किया है, यह भारत में विनिर्माण स्थापित करने के लिए फर्स्ट सोलर जैसी कंपनियों के लिए एक आदर्श अवसर बनाता है। मुझे लगता है कि अगर भारत ने जो किया है, अगर हर देश उसे अपना सकता है और उसका अनुकरण कर सकता है, तो दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्य उद्देश्यों को पूरा करने की हमारी क्षमता कोई समस्या नहीं होगी।

जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल ने कहा कि यह एक उत्कृष्ट बैठक थी। हमने प्रौद्योगिकी और भारत में आने वाले नीतिगत सुधारों में विश्वास और निवेश के नजरिए से भारत में अपार संभावनाओं के बारे में बात की।

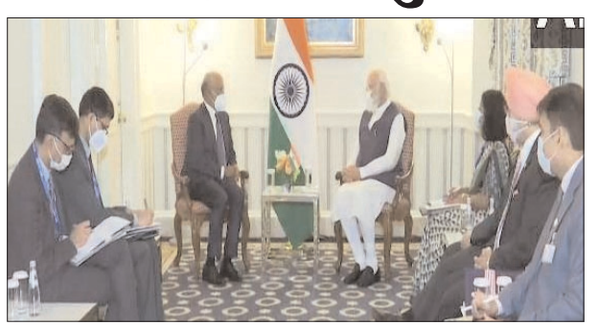

यह बैठकों की श्रृंखला का हिस्सा है, जो पीएम मोदी उन चुनिंदा कारपोरेट प्रमुखों के साथ करेंगे, जिनमें भारत में महत्वपूर्ण निवेश करने की क्षमता है। क्वालकाम एक बहुराष्ट्रीय फर्म है, जो सेमीकंडक्टर्स, सॉफ्टवेयर और वायरलेस टेक्नोलॉजी सर्विस देने वाली कंपनी है। मीटिंग में दौरान भारत में निवेश को लेकर बातचीत हो सकती है।

इसके बाद पीएम मोदी की भारतीय मूल की अमेरिका की उप राष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ द्विपक्षीय बैठक होनी है। उपराष्ट्रपति के समारोह कार्यालय में बैठक भारत समयानुसार में शुक्रवार 12.45 बजे होगी। बैठक बंद कमरे में होगी, लेकिन शुरू होने से पहले उसे देखने के लिए एक मीडिया पूल की अनुमति दी जाएगी और नेता बयान दे सकते हैं। कमला हैरिस और पीएम मोदी के बीच अब तक केवल एक फोन कॉल के माध्यम से बातचीत की हुई। हालांकि उपराष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद उन्होंने कई विश्व नेताओं से बात की थी, उन्होंने जून में ही पीएम मोदी के साथ फोन पर बातचीत की थी, जब उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत से टीके भेजने की पेशकश पर चर्चा की थी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी थी।

पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी जापान के पीएम योशिहिडे सुगा के साथ भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जापान और आस्ट्रेलिया भी क?वाड ग्रुप का हिस्सा हैं। भारत और अमेरिका भी क?वाड में शामिल हैं। ज्ञात हो कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के निमंत्रण पर पीएम नरेंद्र मोदी 23 से 25 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर हैं। उनकी मुलाकात जो बाइडन के साथ भी होगी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी की पहली बड़ी विदेश यात्रा है। इस दौरान पीएम मोदी 24 सितंबर को संयुक?त राष?ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी गुरुवार सुबह भारतीय समयानुसार करीब साढ़े तीन बजे जब वाशिंगटन पहुंचे, तब वहां पर मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने सभी लोगों का शुक्रिया कहा, साथ ही सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी साझा की।

महंत केस की जांच के टेकओवर की प्रक्रिया शुरू

पांच सदस्यों वाली सीबीआई की टीम पहुंची प्रयागराज

लखनऊ एजेंसी।

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत मामले में योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने मामले की जांच के लिए केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश की है।

जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम प्रयागराज की टीम में पांच सदस्य हैं। केस हैंडओवर लेने से पहले सीबीआई की एक टीम केस की जानकारी ले रही है। सीबीआई एफआईआर की कॉपी लेने के लिए पुलिसलाइन पहुंची है। पुलिस लाइन में एसआईटी टीम और प्रयागराज पुलिस के आलाधिकारी भी मौजूद हैं। जल्द ही सीबीआई केस को अपने हाथ में लेकर जांच शुरू करेगी। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना चाहती है और निष्पक्ष जांच को देखते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की है।

नई दिल्ली (एजेंसी)।

संदीप तिवारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में तीसरे आरोपी को एसआईटी ने सीजेएम कोर्ट में गुरुवार को पेश कर दिया। संदीप की बुधवार गिरफ्तारी की गई थी। कोर्ट ने संदीप को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में आरोपी आनंद गिरि, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी तीनों को ही नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। महंत नरेंद्र गिरि ने सुसाइड नोट में तीनों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद यूपी पुलिस ने आनंद तिवारी को हरिद्वार और आद्या व संदीप तिवारी को प्रयागराज से गिरफ्तार किया था। वहीं गुरुवार को संदीप की सीजेएम कोर्ट में पेशी के दौरान उसके वकील ने जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया।

शव फंदे पर तो कैसे चलता रहा पंखा

प्रयागराज, (एजेंसी)। महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध हाल में मौत के मामले में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जो घटना के ठीक बाद पुलिस के पहुंचने के दौरान का है। इसमें फर्श पर महंत का शव पड़ा दिखाई दे रहा है और कमरे का पंखा चल रहा है। वीडियो में आईजी केपी सिंह इस

महंत की मौत से संबंधित एक और वीडियो आया सामने

नई दिल्ली (एजेंसी)।

रहने वाले शिष्यों से पूछताछ करते भी दिख रहे हैं। यह वीडियो उस कमरे का है, जिसमें महंत का शव फंदे पर लटका मिला। वीडियो शुरू होते ही महंत नरेंद्र गिरि का शव फर्श पर पड़ा दिखता है और बगल में ही सुसाइड नोट में उत्तराधिकारी बताए गए बलबीर गिरि खड़े नजर आते हैं। अगले फ्रेम में एक फोटोग्राफर और दरोगा नजर आते हैं। इसके बाद कैमरा बिस्तर और तस्वीरों की ओर घूमता है। अगले फ्रेम में कैमरा कमरे में लगे पंखे की तरफ किया जाता है, जिसमें पंखा चलता हुआ दिखाई देता है। पंखे की रॉड जिस चुल्ले में फंसी होती है, इसी चुल्ले में पीले रंग की नॉयलॉन की उस रस्सी का एक हिस्सा भी फंसा नजर आता है, जिससे बनाए गए फंदे पर महंत का शव लटका मिला। वीडियो में फर्श पर मृत पड़े महंत के गले में रस्सी का एक टुकड़ा भी फंसा दिखाई देता है। कुछ ही देर बाद आईजी केपी सिंह कमरे के दरवाजे पर खड़े महंत के शिष्यों से यह पूछताछ करते नजर आते हैं कि पंखा चल रहा था या इसे किसी ने चलाया। इस पर सुमित नामक शिष्य यह कहता है कि पंखा उसने चलाया।

आनंद गिरि और आद्या तिवारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी पेशी

प्रयागराज, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए आनंद गिरि और आद्या प्रसाद तिवारी ने अपने ऊपर जान का खतरा बताते हुए प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। मामले में सीजेएम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आनंद गिरि और आद्या प्रसाद तिवारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होगी। कोर्ट ने अगले आदेश तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी का आदेश दिया है। दरअसल आनंद गिरि और आद्या प्रसाद तिवारी की ओर से अर्जी दाखिल कर विशेष सुरक्षा की मांग की गई थी। सीजेएम कोर्ट ने जेल मैनुअल व अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया है। आरोप है कि बुधवार को पेशी के दौरान आनंद गिरि और आद्या प्रसाद तिवारी के साथ धक्का-मुक्की हुई थी।

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, डोर-टू-डोर वैक्सीनेशन की अनुमति; नई गाइडलाइंस जारी

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। टीकाकरण का आंकड़ा भी 83 करोड़ के पार हो गया है। इस बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए घर-घर (डोर-टू-डोर) टीकाकरण की अनुमति दे दी है। इसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस में इसकी जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के लिए घर पर टीकाकरण शुरू कर रहे हैं, जो कोविड सेंटर पर जाने में सक्षम नहीं हैं। इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। आदेश में कहा गया है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने में अक्षम लोगों को टीका लगाना सुनिश्चित किया जाए। सभी राज्य और केंद्रशासित राज्य इसके लिए खास व्यवस्था करें।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि कुछ राज्यों में वैक्सीनेशन पर जबरदस्त काम हुआ है। इस वजह से 18 साल से अधिक उम्र के 66 फीसद लोगों को कोरोना का कम से कम एक डोज लग चुका है। 23 फीसद को दोनों डोज लग गए हैं। 6 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी 100 फीसद आबादी को पहला डोज लगा दिया है। इनमें लक्षद्वीप, चंडीगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम शामिल हैं। 4 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 90 फीसद से ज्यादा आबादी को पहला डोज लगाया गया है। इनमें दादरा और नगर हवेली, केरल, लद्दाख और उत्तराखंड हैं।

भारत में बच्चों को कब से लगेगी वैक्सीन - बता दें कि देश में 12 से 17 साल तक के बच्चों को टीकाकरण अगले महीने शुरू हो सकता है। बताया जा रहा है कि कैडिला हेल्थकेयर अगले महीने बच्चों की वैक्सीन जायकोव-डी लॉन्च कर देगी। इसके इमरजेंसी यूज के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पिछले महीने मंजूरी दे दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक जायडस कैडिला अक्टूबर से हर महीने 1 करोड़ डोज बनाना शुरू कर देगी। दूसरी तरफ भारत बायोटेक भी बच्चों पर कोवैक्सिन का तीसरे फेज का ट्रायल पूरा कर चुकी है। कंपनी ने कहा है कि वह अगले हफ्ते थर्ड फेज के डेटा डीजीसीआई को सौंप देगी।

उरी में सुरक्षाबलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर, पांच एके-47 और 70 हैंड ग्रेनेड बरामद

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में उरी के नजदीक रामपुर सेक्टर में गुरुवार को भारतीय सुरक्षाबलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की. यहां पर सुरक्षाबलों ने तीन आतंकियों को ढेर कर दिया और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किया गया. सेना के अधिकारियों का कहना है कि ये आतंकी हाल ही में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भारतीय सीमा में घुसे थे. लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडेय ने कहा कि गुरुवार को हाथलंगा के जंगलों में घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षाबलों ने नाकाम कर दिया. मारे गए आतंकियों में से एक पाकिस्तानी है, बाकी के बारे में पता लगाया जा रहा है. आतंकियों के पास से पांच एके-47 राइफल, सात पिस्तौल, 5 एके-47 की मैगजीन, 24 यूबीजीएल ग्रेनेड, 38 चीनी हथगोले, सात पाकिस्तानी ग्रेनेड और 35000 पाकिस्तानी मुद्रा बरामद की गई है.

सेना के चिनार कोर मुख्यालय में मीडिया को जानकारी देते हुए जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा कि हाल ही में नियंत्रण रेखा के दूसरी तरफ से घुसपैठ की गतिविधियां बढ़ी हैं. उन्होंने कहा, 'हालांकि साल की शुरुआत से कोई घुसपैठ नहीं हुई है. थोड़ी बहुत गतिविधियां हुई हैं जो पाकिस्तानी सेना के कमांडरों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती.' लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने कहा कि घुसपैठ की यह कोशिश बृहस्पतिवार को नाकाम की गई और यह उससे पहले 18-19 सितंबर को हुए प्रयास से अलग है. नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध गतिविधियों का पता चलने के बाद सेना द्वारा उरी सेक्टर में शुरू किया गया तलाशी अभियान कई दिनों से जारी है. हालांकि टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं.

भारतीय सेना को मिलेंगे और 118 अर्जुन टैंक

हंटर किलर से कांपेंगे दुश्मन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय सेना की ताकत में और इजाफा होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार थल सेना के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैवी वेहिकल्स फैक्टरी (एचवीएफ) से नई क्षमताओं से लैस 118 मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन एके-1ए खरीदेगी। सेना की लड़ाकू क्षमताओं में इजाफे के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को 7,523 करोड़ की लागत से भारतीय सेना की खातिर 118 मुख्य युद्धक टैंक (एमबीटी) अर्जुन की खरीद को लेकर एक करार को अंतिम रूप दिया। मंत्रालय ने अर्जुन एमके-1ए टैंकों के लिए हेवी व्हीकल फैक्टरी, अवडी, चेन्नई को यह ऑर्डर दिया है। यह एमबीटी एमके-1ए अर्जुन टैंक का नया संस्करण है, इसमें 72 नई विशेषताएं हैं। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को भारतीय थल सेना के लिए 118 मुख्य युद्धक टैंक (एमबीटी) अर्जुन एमके -1 ए की आपूर्ति के लिए हेवी व्हीकल फैक्ट्री, अवडी, चेन्नई को एक ऑर्डर दिया।

सरकार ने दिया सप्लाई का ऑर्डर

एमके-1ए सटीक मारक क्षमता वाला टैंक

मंत्रालय ने कहा कि एमके-1ए सटीक मारक क्षमता वाला टैंक है और सभी तरह के क्षेत्रों में गतिशीलता में सक्षम तथा उन्नत प्रौद्योगिकी प्रणालियों से लैस है। यह दिन और रात, दोनों स्थिति में दुश्मन से मुकाबला कर सकता है। इसने कहा कि हेवी व्हीकल्स फैक्टरी को मिले इस आर्डर से एमएसएमई सहित 200 से अधिक भारतीय कंपनियों के लिए रक्षा निर्माण में एक बड़ा अवसर खुलेगा और करीब 8,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों की दिशा में बड़ा कदम है। पीएम मोदी ने पहला एमके-1ए टैंक 14 फरवरी 2021 को थल सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवने को चेन्नई में सौंपा था।

भारत ने जो किया, अन्य देश नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सराहा

कहा- आज हम बहुत खुश

नई दिल्ली ■ एजेंसी

कोरोना से निपटने में केंद्र सरकार के इंतजामों और कोविड से मरने वाले परिजनों को 50 हजार रुपए देने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुशी जाहिर की है।

कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 50 हजार रुपए देने के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हम बहुत खुश हैं और भारत ने जो किया है, ऐसा किसी अन्य देश ने नहीं किया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस फैसले पर विचार किया और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 4 अक्टूबर फैसला सुनाएगा। केंद्र सरकार के मुआवजा देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुशी जताई और कहा कि भारत ने जो किया है, कोई अन्य देश नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम से उन लोगों के परिजनों को थोड़ी सांत्वना मिलेगी, जिन्होंने अपनों को खोया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 50 हजार रुपए मिलेंगे।

असम में अतिक्रमण हटाने के दौरान बड़ा बवाल, दो की मौत, 10 जखमी, घायलों में ज्यादातर पुलिस के जवान

मंगलदाई/गुवाहाटी । असम में अतिक्रमण हटाने को लेकर एकबार फिर बड़ा बवाल हुआ है। समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक असम के दरांग जिले के ढोलपुर में गुरुवार को पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई जिसमें कम से कम दो प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है जबकि कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं। घायलों में ज्यादातर पुलिसकर्मी बताए जाते हैं। घायलों में कई की हालत बेहद नाजुक बताई जाती है। बताया जाता है कि घटना के दौरान कई पुलिसकर्मी फायरिंग करते नजर आए...

रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग असम के दरांग जिला प्रशासन की ओर से बेदखल किए गए 800 परिवारों के पुनर्वास की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक प्रदर्शनकारियों और पुलिस बल के बीच झड़प शुरू हो गई। बाद में बल की ओर से की गई फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गई जबकि कम से कम दस अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बेदखल किए गए परिवारों ने सिपझार में विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि बेदखली को रोका जाए और उन्हें एक व्यापक पुनर्वास पैकेज प्रदान किया जाए।

दरांग के पुलिस अधीक्षक सुशांत बिस्वा सरमा ने कहा कि परेशानी तब शुरू हुई जब धारदार हथियारों से लैस प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और आम लोगों पर हमला बोल दिया। बकौल सुशांत बिस्वा सरमा पुलिस के जवानों ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। दोनों पक्षों में हुई झड़प में कम से कम 10 लोग घायल हो गए। घायलों में अधिकांश पुलिसकर्मी हैं।

सुशांत बिस्वा सरमा ने बताया कि जख?मी लोगों का इलाज कर रहे चिकित्सकों ने सहायक उप निरीक्षक मोनीरुद्दीन की हालत बेहद नाजुक बताई है। उन्हें गुवाहाटी मेडिकल कालेज अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। मृतकों की पहचान सद्दाम हुसैन और शेख फरीद के रूप में हुई है। पुलिस ने कड़ी मशक?कत के बाद में स्थिति पर काबू पाया और भीड़ तितर-बितर किया। पुलिस से झड़प के बाद इलाके में तनाव है। इसके बावजूद धौलपुर-I और धौलपुर-III गांवों में बेदखली का काम जारी है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में कहा कि प्रशासन की ओर से बेदखली की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगेगी। पुलिस को अवैध अतिक्रमणकारियों से जमीन को खाली कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिसकर्मी काम पूरा होने तक तैनात रहेंगे। अंधेरा होने पर अतिक्रमण हटाने का काम बंद हो जाएगा और शुक्रवार को फिर से शुरू होगा। वहीं अधिकारियों ने बताया कि दारांग जिला प्रशासन ने सोमवार से 602.04 हेक्टेयर जमीन खाली कराई है। इसमें 800 परिवारों को बेदखल किया गया है। यही नहीं चार अवैध रूप से निर्मित धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया गया है।

सियासत | बन रहा एक और चीन विरोधी गठबंधन, ऐसे कैसे कम होगी ड्रैगन की दादागीरी?

ऑकस में भारत को शामिल नहीं करेगा अमेरिका

वाशिंगटन ■ एजेंसी

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ मिलकर एक नया गठबंधन बनाया है, जिसका नाम है ऑकस। अमेरिका ने इस त्रिपक्षीय गठबंधन ऑकस (एयूकेयूएस) में भारत या जापान को शामिल किए जाने की संभावना को खारिज कर दिया है। अमेरिका ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि वह इस नए गठबंधन में भारत को शामिल नहीं करेगा। मगर यहां सवाल उठता है कि चीन विरोधी गठबंधन ऑकस में क्या भारत को शामिल किए बिना ही अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ड्रैगन की दादागिरी को अमेरिका कम कर पाएगा।

दरअल, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछले हफ्ते ऑकस की घोषणा केवल सांकेतिक नहीं थी और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रो को यही संदेश दिया है कि हिंद-प्रशांत की सुरक्षा के लिए बनाए गठबंधन में किसी अन्य देश को शामिल नहीं किया जाएगा। साकी ने कहा कि भारत या जापान को इस गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा।

भारत के लिए यह झटका, अभी कहना मुश्किल

अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के इस गुट में भारत का शामिल न होना फिलहाल झटका होगा या नहीं, यह कहना मुश्किल है। मगर जिस तरह से पनडुब्बी डील को लेकर अमेरिका और फ्रांस के बीच तनातनी है,अमेरिका उस क्वाड को तवज्जो देना कम कर सकता है, जो चीन के वर्चस्व को कम करने के लिए बना है। क्वाड में भारत और फ्रांस शामिल हैं। अगर अमेरिका ऑकस को ज्यादा तरजीह देना शुरू करता है तो ऐसे में क्वाड का मिशन डगमगा सकता है। हालांकि, क्वाड को लेकर भारत की ओर से कहा गया है कि ऑकस के गठन से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने की थी घोषणा

अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद-प्रशांत में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र के लिए नए त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन ऑकस (एयूकेयूएस) की 15 सितंबर को घोषणा की थी, ताकि वे अपने साझा हितों की रक्षा कर सकें और परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियां हासिल करने में ऑस्ट्रेलिया की मदद करने समेत रक्षा क्षमताओं को बेहतर तरीके से साझा कर सकें। इस समझौते के कारण उसने फ्रांस से अनुबंध रद्द किया है।

भारत में त्योहारी सीजन के दौरान आईईडी के जरिए बड़े ब्लास्ट की फिराक में आईएसआई , खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट

नई दिल्ली,एजेंसी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में बड़ा आतंकी हमला करने की फिराक में है. देश की खुफिया एजेंसियों ने खतरे का अंदेशा जारी करते हुए अलर्ट जारी किया है. सूत्रों के मुताबिक, खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि टिफिन बॉक्स में आईईडी रखकर किसी बड़े हमले को अंजाम दिया जा सकता है. देश को दहलाने के लिए किसी भीड़-भाड़ वाले इलाके में ब्लास्ट करने का प्लान किया जा रहा है.

त्योहारों के सीजन को देखते हुए हमले का प्लान बनाया गया है. इसको अंजाम देने के लिए भारी संख्या में पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुसपैठ करने की कोशिश भी कर सकते हैं. बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया था. पुलिस ने छह आतंकियों को गिरफ्तार किया था. जिनमें से दो आतंकियों का पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई है. हालांकि सबसे बुरी बात यह थी कि गिरफ्तार किए गए सभी 6 भारतीय थे और बहकावे में आकर अपने ही देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे.

अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी कैंप में हलचल बढ़ गई है. सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक, इनके मास्टरमाइंड भारत में आतंकियों को घुसपैठ कराने की साज़िशों में लग गए हैं. जानकारी के मुताबिक PoK में तीन नए टेरर कैंप को एक्टिव किया गया है जिससे अब टेरर कैम्प की संख्या 17 से बढ़ कर 20 हो गई है.

सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक भारत-पकिस्तान के बीच फरवरी में हुए सीजफायर के बाद से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी एक बार फिर से आतंकियों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराने की साजिशों में लग गई हैं.

सार समाचार

फ्रांस ने ईयू को यूएनएससी की सीट देने की खबरों को किया खारिज, कहा- सीट हमारी है और हमारी ही रहेगी

फ्रांस ने यूरोपीय संघ (ईयू) को यूएनएससी यानि की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी सीट को छोड़ने के बारे में अफवाहों का खंडन किया है। फ्रांस ने उन सभी रिपोर्टों का खारिज कर दिया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों यूरोपीय सेना के लिए यूरोपीय संघ के कुछ देशों से समर्थन के बदले में यूएनएससी में अपनी सीट यूरोपीय संघ को देने के लिए तैयार होंगे। हालांकि, फ्रांस ने ऐसी किसी भी योजना से साफ इनकार किया है। फ्रांसीसी सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि, हम औपचारिक रूप से इससे इनकार करते हैं। सीट हमारी है और हमारी ही रहेगी।' बता दें कि यह खबर ऐसे समय आई है जब फ्रांस ऑस्ट्रेलिया द्वारा अमेरिका और ब्रिटेन के साथ एक नए रक्षा समझौते के लिए 66 अरब डॉलर के पनडुब्बी सौदे को टालने से नाराज था। इस घोषणा ने फ्रांस को चौंका दिया था जिसके बाद से मैक्रों यूरोपीय देशों को एक करीबी सैन्य एकीकरण के लिए एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं।

अल्जीरिया ने मोरक्को के विमानों के लिए बंद किये एयरस्पेस

अल्जीयर्स। बढ़ते राजनयिक मतभेदों के बीच अल्जीरिया ने अपने हवाई क्षेत्र को मोरक्को के सभी नागरिक और सैन्य विमानों के लिए बंद कर दिया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने एक आधिकारिक बयान का हवाला देते हुए कहा कि अल्जीरियाई राष्ट्रपति अब्देलमदजिद तेब्बौने ने बुधवार को उच्च सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता के बाद यह निर्णय लिया। बयान के अनुसार, परिषद ने अल्जीरियाई हवाई क्षेत्र को सभी मोरक्कन नागरिक और सैन्य विमानों के साथ-साथ मोरक्कन पंजीकरण संख्या वाले लोगों के लिए तत्काल बंद करने का निर्णय लिया है। अल्जीरिया ने अगस्त में मोरक्को के साथ राजनयिक संबंधों को तोड़ दिया था। मोरक्को ने बाद में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध तोड़ने के अल्जीरिया के पूरी तरह से अनुचित निर्णय पर खेद व्यक्त किया था।

संयुक्त राष्ट्र सत्र में प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा तालिबान

नई दिल्ली। अफगानिस्तान के नए तालिबान शासकों के संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के मौजूदा सत्र में बोलने या अपने देश का प्रतिनिधित्व करने की संभावना नहीं है। पूर्व अफगान सरकार के प्रतिनिधि अभी भी संयुक्त राष्ट्र में अफगान मिशन पर अपना नियंत्रण बनाए हुए हैं। मंगलवार को, वे उस सत्र में शामिल हुए, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संबोधित किया था। एक राजनयिक सूत्र ने कहा, वे तब तक मिशन पर कब्जा करना जारी रखेंगे, जब तक कि क्रेडेंशियल कमेटी कोई निर्णय नहीं ले लेती। 15 सितंबर को, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को वर्तमान में मान्यता प्राप्त अफगान राजदूत, गुलाम इसकजई से एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया था कि वह और उनकी टीम के अन्य सदस्य यूएनजीए सत्र में अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगे। 20 सितंबर को, तालिबान-नियंत्रित अफगान विदेश मंत्रालय ने भी गुटेरेस को एक संचार भेजा, जिसमें वर्तमान यूएनजीए में भाग लेने का अनुरोध किया गया था। तालिबान नेता, अमीर खान मुत्ताकी ने नए अफगान विदेश मंत्री के तौर पर पत्र पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने न्यूयॉर्क में पत्रकारों से बात करते हुए दोनों पत्र प्राप्त करने की पुष्टि की है।

सुरक्षा परिषद ने सूडान में तख्तापलट के प्रयास की निंदा की

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा सूडान में तख्तापलट के प्रयास की कड़े शब्दों में निंदा की है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, एक बयान में, सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक के प्रति अपना पूर्ण समर्थन दोहराया है।
परिषद के सदस्यों ने सभी हितधारकों से राष्ट्रीय संकट और संक्रमण के मुद्दे - आगे का रास्ता नामक राष्ट्रीय पहल के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने का आग्रह किया, और आगे सूडान के नागरिक और सैन्य अभिनेताओं को प्रतिबद्ध रहने और सहयोग की भावना में काम करना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने सूडान के लोगों के साथ अपनी एकजुटता भी व्यक्त की और सूडान की संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय एकता के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मंगलवार को तख्तापलट के प्रयास की निंदा की। गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने एक बयान में कहा, सूडान के राजनीतिक संक्रमण को कमजोर करने का कोई भी प्रयास राजनीतिक और आर्थिक मोचरें पर की गई कड़ी मेहनत की प्रगति को खतरे में डाल देगा। महासचिव ने सभी दलों से संक्रमण के लिए प्रतिबद्ध रहने और सूडानी लोगों की आकांक्षाओं को एक समावेशी बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहने का आह्वान किया।

यमन के शबवा प्रांत में लड़ाई अभी जारी

सना। एक सैन्य अधिकारी ने कहा कि देश के तेल समृद्ध प्रांत शबवा पर नियंत्रण को लेकर यमन के सरकारी बलों और हाउती विद्रोहियों के बीच लड़ाई जारी है। अधिकारी ने बुधवार को समाचार एजेंसी को बताया कि सरकार ने शबवा के पश्चिमी हिस्सों में विद्रोहियों के साथ क्रूर लड़ाई छेड़ने वाले बख्तरबंद वाहनों द्वारा समर्थित भारी सुदृढीकरण भेजा। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान, दोनों पक्षों के कई लोग या तो मारे गए या घायल हो गए, क्योंकि लड़ाई और अधिक बढ़न रही है। सरकारी बलों ने कई सैन्य इकाइयों को तैनात किया और शबवा के कुछ क्षेत्रों में हाउतीयों की प्रगति को रोकने में कामयाब रहे। इस बीच, देश के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बयान जिले में सेना की आग से दर्जनों हाउती लड़ाके मारे गए, साथ ही उनके कई बख्तरबंद वाहनों को नष्ट कर दिया। सरकार समर्थक मंत्रालय ने पुष्टि की कि बड़े सैन्य सुदृढीकरण और सैकड़ों आदिवासी लड़ाके इस क्षेत्र में सेना की सेना का समर्थन करने और हाउतीयों को शबवा पर हमला करने से रोकने के लिए पहुंचे।

अमेरिकी सांसद बोले- पीएम मोदी का स्वागत करने में गौरवान्वित महसूस कर रहा है अमेरिका

जिनेवा। (एजेंसी)।

अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद ने सदन में कहा कि अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करके गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के राज के सिद्धांतों से गहरे जुड़े हुए हैं।प्रधानमंत्री मोदी बुधवार से शुरू होने वाली तीन दिवसीय अमेरिका यात्रा पर गए हैं जहां वह राष्ट्रपति जो बाइडन से मुलाकात करेंगे और ऐतिहासिक क्वाड सम्मेलन में भाग लेंगे।

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य अर्ल ''बड़ी'' कार्टर ने सदन में कहा, ''अध्यक्ष महोदया, मैं अमेरिका और भारत के बीच महत्वपूर्ण कूटनीतिक साझेदारी को मान्यता देने के लिए खड़ा हुआ हूं।''उन्होंने कहा, ''हमारे नेताओं के दौरे, हमारे संबंधों के लिए अहम हैं और प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर अमेरिका गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संबंध लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के राज के सिद्धांतों से गहरे जुड़े हुए हैं।'' कार्टर ने कहा कि इतने सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार सहयोग बढ़ा है और यह साझेदारी का महत्वपूर्ण अंग है। भारत और अमेरिका के बीच 2019 में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार 149 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था।

पाकिस्तान के जिगरी तुर्की ने कश्मीर का मुद्दा उठाया, विदेश मंत्री जयशंकर ने साइप्रस का जिक्र कर ऐसे चुप कराया

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

कश्मीर के मसले को लेकर मुस्लिम देशों को साथ लेकर लॉबिंग करने में लगा है। जिसमें ईरान, तुर्की, मलेशिया जैसे देश शामिल हैं और उन्हें चीन का भी समर्थन हासिल है। पाकिस्तान की ये लगातार कोशिश रहती है कि वो किस तरह से कश्मीर के मसले को वैश्विक मंच पर उठाए। इस तरह की हिमाकत पाकिस्तान ने कई बार की भी है। पाकिस्तान के दोस्त तुर्की कुछ इसी तरह की हरकत संयुक्त राष्ट्र के मंच पर दोहराने की कोशिश की लेकिन कश्मीर का मुद्दा उठाना उसके लिए बहुत भारी पड़ गया। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन को भारत के विदेश मंत्री ने करारा जवाब दिया है।

तुर्की के राष्ट्रपति की पाकिस्तानी जुबान

रजब तैयब एर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र में वैश्विक नेताओं के नाम अपने संबोधन में एक बार फिर जम्मू- कश्मीर का मुद्दा उठाया। एर्दोआन ने सामान्य चर्चा में अपने संबोधन में कहा, हमारा मानना है कि कश्मीर को लेकर 74 साल से जारी समस्या को दोनों पक्षों को संवाद और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के जरिये हल करना चाहिए। अतीत में भी एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाया था जिसपर भारत ने आपत्ति जताई थी। पिछले साल पाकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान भी कश्मीर का मुद्दा उठाने पर उस समय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि एर्दोआन की टिप्पणी न तो इतिहास की समझ और न ही कूटनीति के संचालन को दर्शाती है और इसका तुर्की के साथ भारत के संबंधों पर गहरा असर पड़ेगा।

जयशंकर ने दिया मुंहतोड़ जवाब

एस जयशंकर ने साइप्रस के अपने समकक्ष निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान जयशंकर ने साइप्रस के संबध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रासंगिक प्रस्तावों का पालन करने की आवश्यकताओं पर जोर दिया। जयशंकर ने क्रिस्टोडौलाइड्स के साथ अपनी मुलाकातों के बारे में ट्वीट करते हुए कहा कि हम आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। सभी को साइप्रस के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का पालन करना चाहिए।

क्या है तुर्की-साइप्रस विवाद

साइप्रस में लंबे समय से चल रहे संघर्ष की शुरुआत 1974 में यूनान सरकार के समर्थन से हुए सैन्य तख्तापलट से हुई थी। इसके बाद तुर्की ने यूनान के उत्तरी हिस्से पर आक्रमण कर दिया था। तुर्की के 35 हजार सैनिक इस क्षेत्र पर तैनात हैं। इस घटना के बाद से साइप्रस 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। इसे केवल तुर्की ने मान्यता दी है। जबकि, ग्रीक नस्ल वाले साइप्रस को यूएन सहित पूरी दुनिया स्वीकार करती है।

यात्रा के लिए टीका प्रमाणन में न्यूनतम मानदंड पूरे होने चाहिए: ब्रिटेन सरकार

लंदन। (एजेंसी)।

ब्रिटेन सरकार ने सभी देशों से कोविड-19 टीका प्रमाणन के 'न्यूनतम मानदंड' पूरे करने को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि वह अपने अंतरराष्ट्रीय यात्रा नियमों को लेकर भारत के साथ 'चरणबद्ध दृष्टिकोण' पर काम कर रही है। यह बयान ऑक्सफोर्ड/एस्ट्राजेनेका के, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड टीके को बुधवार को ब्रिटेन के विस्तारित यात्रा परामर्श में स्वीकार किए जाने के बाद आया है। बहरहाल, भारत का टीका प्रमाणन 18 स्वीकृत देशों की सूची में शामिल नहीं होने की वजह से, ब्रिटेन आने वाले भारतीय यात्रियों के टीकाकरण को स्वीकार नहीं कियाजाएगा और इसीलिए उन्हें आगमन के बाद 10 दिनों तक पृथक-वास में रहने की अनिवार्यता को पूरा करना होगा।

ब्रिटेन के नए अद्यतन यात्रा परामर्श से पृथकवास नियमों को लेकर कुछ भ्रम फैला, खासकर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड टीके को लेकर, जिसका भारत अपने यहां टीकाकरण कार्यक्रम में व्यापक इस्तेमाल कर रहा है। ब्रिटेन द्वारा यात्रा परामर्श में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड/एस्ट्राजेनेका के टीके कोविशील्ड को शामिल करने नहीं करने पर काफी आलोचना हुई थी। इस प्रक्रिया पर अत्यधिक भ्रम के बाद, ब्रिटेन सरकार के सूत्रों ने बुधवार रात कहा कि स्वीकृत देशों की सूची में जोड़ या परिवर्तनों पर नियमित रूप से विचार किया जा रहा है, लेकिन देश के टीका प्रमाणीकरण को मंजूरी देने के लिए आवश्यक मानदंडों पर कोई और स्पष्टता नहीं दी गई। ब्रिटेन सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, 'हमारी हाल ही में विस्तारित अंदरूनी टीकाकरण नीति के हिस्से के रूप में, हम अंतरराष्ट्रीय यात्रा के उद्देश्यों के लिए फाइजर बायोएनटेक, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, मॉडर्न और जेनसेन (जे एंड जे) के टीकों को मान्यता देते हैं। इसमें अब एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका वैक्सजेवरिया और मॉडर्ना टाकेडा भी शामिल किए जा रहे हैं।'

प्रवक्ता ने कहा, 'हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने, और सुरक्षित एवं टिकाऊ तरीके से यात्रा को फिर से खोलना है, यही वजह है कि सभी देशों से टीका प्रमाणन को सार्वजनिक स्वास्थ्य और व्यापक विचारों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मानदंडों को पूरा करना चाहिए। हम अपने चरणबद्ध दृष्टिकोण को लागू करने के लिए भारत सहित अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ काम करना जारी रख रहे हैं। जिन यात्रियों को पूरी तरह से टीका नहीं लगाया गया है, या भारत जैसे देश में टीका लगाया गया है, जो वर्तमान में ब्रिटेन सरकार की मान्यता प्राप्त सूची में नहीं है, उन्हें प्रस्थान से पहले जांच करानी होगी, इंग्लैंड में आगमन के बाद दूसरे और आठवें दिन की पीसीआर जांचों के लिए भुगतान करना होगा और स्वयं को एकांतवास में रखना होगा। उन्हें पांच दिन बाद पीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट देने के बाद इससे छूट मिलने का विकल्प होगा।

भारत में दिए जाने वाले दो मुख्य कोविड-19 टीकों में से कोविशील्ड के एक होने के बावजूद भारत के टीकाकरण प्रमाणन को मान्यता नहीं दिए जाने के संदर्भ में, ब्रिटेन सरकार के सूत्र ने केवल यही कहा कि अन्य देशों और क्षेत्रों में उसके अंदरूनी टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा एक चरणबद्ध दृष्टिकोण पर आधारित रही है। गौरतलब है कि, ब्रिटेन की यात्रा के संबंध में फिलहाल लाल, एम्बर और हरे रंग की तीन अलग अलग सूचियां बनाई गई हैं। कोविड-19 खतरे के अनुसार अलग-अलग देशों को अलग अलग सूची में रखा गया है। चार अक्टूबर से सभी सूचियों को मिला दिया जाएगा और केवल लाल सूची बाकी रहेगी। लाल सूची में शामिल देशों के यात्रियों को ब्रिटेन की यात्रा पर पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। भारत अब भी एम्बर सूची में है। इस सूची में शामिल देशों के यात्रियों को ब्रिटेन जाने पर कुछ पाबंदियों से गुजरना पड़ सकता है।

श्रीलंका में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में प्रचार गतिविधियों की योजना बनाई

कोलंबो (एजेंसी)।

दक्षिण एशियाई देश में कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और पर्यटन व्यापार शो में प्रचार गतिविधियां शुरू करने की योजना बनाई है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, श्रीलंका के व्यापार शो इस साल फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी में आयोजित होने वाले हैं। श्रीलंका पर्यटन विकास प्राधिकरण (एसएलटीडीए) की अध्यक्ष किमरली फर्नांडो ने कहा, जिन तीन व्यापार शो में हम भाग लेने की योजना बना रहे हैं, जो कोविड महामारी की शुरूआत के बाद एक साल के लंबे ब्रेक बाद हैं, जो विश्व स्तर पर पर्यटन स्थलों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। फर्नांडो ने कहा, हमें उम्मीद है कि श्रीलंका उद्योग को पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए उन सभी में भाग लेने में सक्षम होगा। इस साल पेरिस में होने वाले इंटरनेशनल फ्रेंच ट्रैवल मार्केट (आईएफटीएम) टॉप रेसा के लिए करीब 200 डेस्टिनेशन, 1,700 ब्रांड्स, 34,000 टूरिज्म प्रोफेशनल्स और 150 कॉन्फ्रेंस सेशन तैयार किए गए हैं। फर्नांडो ने कहा कि फ्रांस अगस्त की शुरूआत में श्रीलंका की यात्रा की अनुमति देने वाले पहले देशों में से एक था, उम्मीद है कि फ्रांसीसी यात्री इस सर्दी में अपने पसंदीदा उष्णकटिबंधीय गंतव्य पर लौट आएंगे। श्रीलंका के पर्यटन प्राधिकरण के प्रमुख ने कहा कि वे ब्रिटेन और जर्मनी में इसी तरह के आयोजनों में भाग लेने पर विचार कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य यूरोप से अधिक यात्रियों को आकर्षित करना है, जो वर्तमान में श्रीलंका में आगंतुकों का सबसे बड़ा स्रोत है। जनवरी में अपनी सीमाओं को फिर से खोलने के बाद से, श्रीलंका ने इस साल के पहले आठ महीनों में 24,337 पर्यटकों का आगमन दर्ज किया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कोविड -19 महामारी की तीसरी लहर के बावजूद, अगस्त में पर्यटकों का आगमन जुलाई से 107 प्रतिशत बढ़कर 5,040 हो गया है।

वायरस ने ली एक दिन में 1900 से अधिक जान, बाइडेन कोविड समिट कर बांट रहे ज्ञान, मौत के मामले में स्पेनिश फ्लू से भी आगे निकला कोरोना

संयुक्त राष्ट्र (एजेंसी)।

कोरोना वायरस की उम्र 1 साल से ज्यादा की हो चुकी है। लॉकडाउन, कर्फ्यू आदि-इत्यादि झेलने के बाद दुनिया अब वैक्सीन नामकर समाधान की ओर बढ़ निकली है। कोरोना की चुनौतियों और इससे निपटने के उपायों को लेकर संयुक्त राष्ट्र कोविड शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया। जिसमें खुद को सुपरपॉवर मुल्क कहने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अमीर देशों से वैक्सीन डोनेशन में और मदद करने की अपील करते नजर आए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया को कोरोना महामारी की चुनौतियों और इससे निपटने के बारे में ज्ञान बांटने वाला अमेरिका ही इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है।

कोरोना से भयावह हालात

अमेरिका में कोरोना वायरस से मार्च के बाद से पहली बार एक दिन में औसतन 1,900 से अधिक मरीजों की मौत हुई और विशेषज्ञों का कहना है कि यह संक्रमण एक अलग समूह यानी टीके की खुराक न लेने वाले 7.1 करोड़ अमेरिकियों को अपना निशाना बना रहा है। देश के राष्ट्रपति जो बाइडन कोविड-19 की इस जानलेवा लहर से निपटने में मदद के लिए लोगों से घर पर संक्रमण की जांच करने का अनुरोध कर रहे हैं। महामारी के कारण अस्पताल क्षमता से अधिक भरे पड़े हैं और देशभर में स्कूलों के बंद होने का खतरा पैदा हो गया है। स्प्रिंगफील्ड-ब्रैनसन इलाके में कॉक्सहेल्थ अस्पतालों में एक हफ्ते में ही 22 लोगों की मौत हो गयी। पश्चिमी वर्जीनिया में सितंबर के पहले तीन हफ्तों में 340 लोगों की मौत हो चुकी है। जॉर्जिया में हर दिन 125 मरीज जान गंवा रहे हैं जो कैलिफोर्निया या किसी अन्य घबी आबादी वाले राज्य से अधिक है।

स्पेनिश फ्लू से भी बड़ी महामारी

अमेरिका में स्पेनिश फ्लू से जितनी मौतें हुई हैं उससे ज्यादा मौतें कोरोना वायरस से हो चुकी हैं। एपी की रिपोर्ट के अनुसार जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के आंकड़ों के तहत अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से 674,000 मौतें हो चुकी हैं। हालांकि, डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में कोरोना की वजह से 669,412 मौते हुई हैं और 41,831,507 केस आ चुके हैं। वहीं, अगर स्पेनिश फ्लू की बात करें तो सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रेवेंशन (सीडीसी) के डेटा के अनुसार, 1918 में फ्लू से अमेरिका में 6,75,000 लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में कुछ रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना स्पेनिश फ्लू से आगे निकल गया है, लेकिन डब्ल्यूएचओ के डेटा के हिसाब से भी आंकड़ा थोड़ा ही पीछे है।

लीबिया और यूएनएचसीआर ने अवैध प्रवास, सीमा नियंत्रण पर चर्चा की

त्रिपोली (एजेंसी)।

लीबिया के प्रेसीडेंसी काउंसिल के उपाध्यक्ष मूसा अल-कोनी ने यहां संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (यूएनएचसीआर) के देश में मिशन के प्रमुख जीन-पॉल कैवेलियरी से मुलाकात की और अवैध प्रवास, दूसरों के बीच सीमा नियंत्रण पर चर्चा की।

प्रेसीडेंसी काउंसिल द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, प्रेसीडेंसी काउंसिल के उपाध्यक्ष ने पुष्टि की है कि अवैध प्रवास मुख्य रूप से एक मानवीय मुद्दा है। उन्होंने इसके सफल समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को एकजुट करने के महत्व पर जोर दिया। बयान के अनुसार, अल-कोनी ने समुद्र के बजाय लीबिया की दक्षिणी सीमा में अवैध प्रवासन के बारे में संबोधित करने के महत्व पर भी जोर दिया, जहां अवैध प्रवासी यूरोप की ओर जाते हैं। कैवेलियरी ने कहा कि लीबिया से अन्य देशों में प्रवासियों को निकालने में समस्याएं आ रही हैं, जिससे उड़ानों को व्यवस्थित करने में विफलता हो रही है। उन्होंने अवैध प्रवास को संबोधित करने के लिए प्रेसीडेंसी परिषद के साथ सहयोग करने की आवश्यकता पर भी जोर देने को कहा है। 2011 में मुअम्मर गद्दाफी के पतन के बाद से लीबिया असुरक्षा और अराजकता का सामना कर रहा है, जिससे उत्तरी अफ्रीकी देश अवैध प्रवासियों के लिए भूमध्य सागर को यूरोपीय तटों पर पार करने के लिए एक पसंदीदा स्थान बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार, अब तक 24,420 अवैध प्रवासियों को बचाया गया है, जबकि मध्य भूमध्य मार्ग पर लीबिया के तट से सैकड़ों अन्य मारे गए और लापता हो गए।

दो साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं मिल रहे जरूरी पोषक तत्व : यूनिसेफ

संयुक्त राष्ट्र (एजेंसी)।

संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को विकास के लिए आवश्यक पर्याप्त भोजन या पोषक तत्व नहीं मिल रहे और साथ ही इसमेंचेतावनी दी गई है कि कोविड-19 महामारी में यह स्थिति और बदतर हो सकती है।

इस सप्ताह होने वाले 'संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली सम्मेलन' से पहले संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) की एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, इस अध्ययन में बच्चों की माताओं से बातचीत की गई और पाया गया कि ऑस्ट्रेलिया, इथियोपिया, घाना, भारत, मेक्सिको, नाइजीरिया, सर्बिया और सूडान में हर तीन में से एक बच्चे को प्रतिदिन कम से कम एक बार प्रसंस्कृत या अति प्रसंस्कृत भोजन या पेय दिया जाता है।

रिपोर्ट में कहा गया कि बढ़ती गरीबी, असमानता, युद्ध, जलवायु संबंधी आपदा और कोविड-19 जैसी स्वास्थ्य आपदाओं के कारण विश्व के कई देशों में बच्चों को उचित पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं और पिछले 10 साल में इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है।

रिपोर्ट में कहा गया, ''हमने 18 देशों में माताओं और पोषण विशेषज्ञों से बातचीत की कि वे बच्चों को भोजन देने का निर्णय कैसे लेते हैं। हमें पता चला कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भारत में माताओं को ऐसे सामाजिक नियमों का पालन करना पड़ता है जिससे वह भोजन खरीदने का निर्णय नहीं ले पाती।''

भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि यास्मीन अली हक ने कहा, ''कोविड-19 के कारण पोषण संबंधी चुनौतियां बढ़ गई हैं। यदि हम बच्चे की पोषण स्थिति को प्रभावित करने वाले बहुक्षेत्रीय निवेश को अधिकतम करना चाहते हैं तो स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं का प्रभावी वितरण महत्वपूर्ण है।

दिल्ली की जनता को आरओ का पानी सप्लाई करेगी केजरीवाल सरकार

पहले चरण में 363 एमएलडी क्षमता के आरओ प्लांट लगाएगी दिल्ली सरकार

नई दिल्ली, प्रफुल्ल राय(शिवालिक)।

दिल्ली सरकार राजधानी में रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। इस योजना को उन क्षेत्र में लागू किया जाएगा, जहां भूजल का स्तर अधिक है, लेकिन खारेपन और टीडीएस के कारण उपयोग करने योग्य नहीं है। दिल्ली के जल मंत्री और दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन ने डीजेबी अधिकारियों के साथ बैठक कर इस परियोजना की तैयारियों का जायजा लिया। साधारण आरओ सिस्टम में, शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाता है, लेकिन दिल्ली सरकार अत्याधुनिक तकनीक से बने आरओ संयंतत्रों का उपयोग करेगी, जिसकी जल रिकवरी दर 80 फीसद होगी। पहले चरण में, 363 मिलियन लीटर प्रति दिन की कुल क्षमता वाले आरओ संयंत्र चिन्हित स्थानों पर लगाए जाएंगे, जहां अधिशेष भूजल उपलब्ध है। इन आरओ प्लांटों में पानी

पहले चरण में, 363 मिलियन लीटर प्रति दिन की कुल क्षमता वाले आरओ संयंत्र चिन्हित स्थानों पर लगाए जाएंगे, जहां अधिशेष भूजल उपलब्ध है। इन आरओ प्लांटों में पानी की आपूर्ति जमीन से पानी निकालकर की जाएगी:-सत्येंद्र जैन

की आपूर्ति जमीन से पानी निकालकर की जाएगी, जिसके बाद घरों में शुद्ध पानी पहुंचाया जाएगा। दिल्ली सरकार इन आरओ संयंत्रों को केवल उन क्षेत्रों में बनाएगी, जहां भूमिगत जल का स्तर अधिक उपलब्ध है, लेकिन पानी की खराब गुणवत्ता के कारण उपयोग में नहीं लाया जा सकता। उदाहरण के लिए, नजफगढ़ क्षेत्र में पानी 2-3 मीटर की गहराई पर ही उपलब्ध है, लेकिन खारेपन की वजह से इस पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता। इस परियोजना के पहले चरण में ओखला, द्वारका, नीलोठी-नांगलोई, चिल्ला और नजफगढ़ को लक्षित किया गया है। दिल्ली सरकार ने इस परियोजना को एक वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के भूजल में 22 लाख मिलियन गैलन लीटर से अधिक खारा पानी है। इस पानी को पीने योग्य बनाने के लिए इसे आरओ से ट्रीट करने की जरूरत है, जिसके बाद इसे घरों तक पहुंचाया जा सकेगा। इस परियोजनाओं को लागू करने के लिए स्थानों को रणनीतिक रूप से चुना गया है, ताकि मौजूदा प्रणाली का उपयोग किया जा सके और नई पाइपलाइन बिछाने की भारी लागत को बचाया जा सके। इस परियोजना को लागत प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली सरकार एक नए मॉडल का पालन करेगी, जहां निजी निवेशक आरओ प्लांट की स्थापना में निवेश करेंगे और दिल्ली जल बोर्ड उनसे निर्धारित दर पर आरओ द्वारा साफ किया गया पानी खरीदेगा।

'सेवा ही समर्पण अभियान' के अंतर्गत तीनों निगमों में चलाए जायेंगे विभिन्न अभियान

नई दिल्ली,(रविशंकर तिवारी)।

दक्षिणी निगम के महापौर मुकेश सुर्यान, उत्तरी निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह, पूर्वी निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने आज सिविक सेंटर में संयुक्त प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाये जा रहे 'सेवा ही समर्पण अभियान' के अंतर्गत दिल्ली के नागरिकों को बेहतर जनसुविधाएं प्रदान करने के लिए तीनों नगर निगम द्वारा विभिन्न अभियान चलाए जायेंगे। इस अवसर पर दक्षिणी निगम के महापौर मुकेश सुर्यान ने कहा कि तीनों निगम विशेष रूप से मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध, सूखा राशन कार्य वितरण, चलो स्कूल प्रोग्राम, कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण, सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाए जायेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा यह लक्ष्य है कि अगले 6 महीने में दिल्ली को कचरा मुक्त किया जाएगा और सभी ढलाव घरों पर कूड़े के निष्पादन के लिए एफ.सी.टी.एस. लगाए जायेंगे। दक्षिणी निगम 1136 आटो टिप्पर द्वारा घर-घर जाकर नियमित रूप से कूड़ा उठाने का कार्य कर रहा है साथ ही बड़ी सड़कों की

सफाई के लिए 24 मैकेनिकल स्वीपर मशीन कार्यरत है। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जायेगा।

उन्होंनें कहा कि दक्षिणी निगम के विद्यालयों में 'चलो स्कूल प्रोग्राम' के तहत् अभी तक 94000 बच्चों का दाखिला हो चुका है। कोरोना महामारी के कारण विद्यालय बंद है और जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए दक्षिणी निगम द्वारा ऑनलाइन क्लास के लिए 5000 टैबलेट वितरित किये जायेंगे। मिड-डे-मिल की जगह बच्चों को सूखा राशन दिया जा रहा है और चारो जोन के विद्यालय में सूखा राशन वितरण कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाया जा रहा हैं।

उत्तरी दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा व समर्पण अभियान के अंतर्गत स्वच्छता अभियान, पौधारोपण अभियान, दिल्ली कूड़ा मुक्त अभियान व प्रदूषण मुक्त अभियान चलाएगी। उन्होंने बताया कि 07 अक्टूबर से उत्तरी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा जिसमें निगम के सभी कर्मचारी, अधिकारी, आरडब्ल्यूए, मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे।

संक्षिप्त खबर

मौलाना कलीम सिद्दीकी को तुरंत रिहा किया जाएः जमाअत इस्लामी हिन्द

नई दिल्ली। मौलाना कलीम सिद्दीकी को यूपीएटीएस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर जमाअत इस्लामी हिन्द के अमीर सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने अपने बयान में मांग की कि मौलाना पर लगे कथित आरोपों को बिना शर्त वापस लिया जाए, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए और उनके साथ न्याय किया जाए। मौलाना कलीम सिद्दीकी न केवल मुसलमानों के बीच बल्कि गैर-मुस्लिम समाज में भी एक सम्मानित व्यक्ति हैं। उनकी गिरफ्तारी से आबादी के एक बड़े हिस्से में बेचैनी फैल गई है। गिरफ्तारी ने एक बार फिर यूपी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसे यूपी में आगामी चुनावों के संदर्भ में हिंदू-मुस्लिम नफरत को बढ़ावा देने का एक निंदनीय प्रयास भी माना जा रहा है। हम हकूमत और पुलिस को यह याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे देश में धर्म और आस्था पर अमल करना और उसका प्रचार करना हर नागरिक का बुनियादी, मानवीय और संवैधानिक अधिकार है। उसी तरह, हमारे संविधान ने प्रत्येक नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता दी है कि वह जो भी विचारधारा या आस्था को पसंद करता है उसे अपनाएं। इन स्वतंत्रताओं को कम करने या प्रतिबंधित करने का कोई भी प्रयास एक अमानवीय और असंवैधानिक प्रयास होगा और इन नापाक प्रयासों का विरोध करना देश के सभी गंभीर नागरिकों की जिम्मेदारी है।

10 करोड़ की हेरोइन बरामद, महिला सहित 3 अफ्रीकी गिरफ्तार

नई दिल्ली। द्वारका जिले के एंटी नारकोटिक्स सेल की पुलिस टीम ने ड्रग्स की सप्लाई करने वाले अफ्रीकियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक महिला भी शामिल है। आरोपियों की पहचान युगांडा की एंजेला नालूनोंदा, नाइजीरिया के इफेदी फ्रैंक ईव और युछे लिविंस डाईक के रूप में हुई है। इनके पास से 811 ग्राम हाई क्वालिटी की हेरोइन बरामद की गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। डीसीपी द्वारका संतोष मीणा के अनुसार जिले में ड्रग्स सिंडिकेट और इसके सप्लायरों की पकड़ के लिए एंटी नारकोटिक्स सेल की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में एंटीनारकोटिक्स पुलिस को उत्तम नगर के पास बड़ी मात्रा में हेरोइन की स्मगलिंग का पता चला था। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए एसीपी ऑपरेशन विजय सिंह यादव की देखरेख में नारकोटिक्स सेल के इंचार्ज सुभाष चंद की टीम ने उत्तम नगर में ट्रैप लगाकर एक अफ्रीकन महिला को हिरासत में लिया। पुलिस ने उसके पास से तलाशी में सफेद रंग की पॉलिथीन में 362 ग्राम फाइन क्वालिटी की हेरोइन बरामद किया, जिसे उसने छुपा रखा था।

फेंडा ऑडियो ने लॉन्च किया पार्टी स्पीकर

नई दिल्ली। फेंडा ऑडियो ने त्योहारी सीजन के लिए नया एफएंडडी पीए 300,100-वाट वाले ब्लूटूथ वायरलेस पार्टी स्पीकर सिस्टम के लॉन्च की घोषणा की है। नया स्पीकर एक पावरफुल परफार्मेंस, मल्टीपल इनपुट्स, कराओके मोड और एक मजबूत पोर्टेबल बॉडी से लैस है। एफएंडडी पीए 300 इनडोर और आउटडोर दोनों तरह के उपयोग के लिए एक उपयोगी स्पीकर है और रिचार्जेबल बैटरी के साथ आता है जो आपको इसे बिना बिजली उपयोग करने की भी आजादी देता है। त्योहारों के मौसम में संगीत की मांग रहती है- चाहे वह भजन हो, एंबिएंट म्यूजिक हो या फिर बॉलीवुड की कुछ लेटेस्ट धुनें। सभी अवसरों के लिए, और विशेष रूप से हाउस पार्टियों के लिए, फेंडा ऑडियो का नवीनतम स्पीकर सिस्टम लोगों को एक साथ एक मंच पर लाने के लिए बनाया गया है। 7 इंच के बड़े वूफर और 2 इंच के ट्वीटर्स से संचालित यह शक्तिशाली स्पीकर 100 वाट एम्पलीफायर के साथ आता है।

10,000 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज में डूबा है डीएमआरसी, 24 सितंबर की बैठक में अहम निर्णय की उम्मीद

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण के लगे झटकों से दिल्ली मेट्रो रेल निगम उबरा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अब उसे दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) 7100 करोड़ रुपये चुकाने हैं। बताया जा रहा है कि इसके कई अन्य मुद्दों को लेकर दिल्ली मेट्रो रेल निगम के निदेशकों की बैठक 24 सितंबर को होगी। इसमें मेट्रो से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्टर के दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) के भुगतान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने नौ सितंबर को डीएमआरसी से कहा था कि वह मध्यस्थता के तहत किए गए निर्णय के आधार पर (डीएएमईपीएल) को 7100 करोड़ रुपये का भुगतान करे। इस निर्णय के बाद यह पहली बैठक है।

सूत्रों की मानें तो डीएमआसी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की बैठक में इस बार एयरपोर्ट मेट्रो के मामले में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भुगतान पर चर्चा होनी तय है। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो पिछले एक साल से तकरीबन 4000 करोड़ रुपये के कर्ज में डूब गई है, क्योंकि इसका संचालन सामान्य रूप से नहीं हो रहा है। आलम यह है कि सिर्फ 100 फीसद सिटिंग कैपिसिटी के साथ ही मेट्रो दिल्ली और एनसीआर में रफ्तार भर रही है। यहां पर बता दें कि डीएमआरसी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में दिल्ली और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं।

गौरतलब है कि लाकडाउन से पहले 24 लाख यात्री दिल्ली मेट्रो में सफर करते थे। पिछले कुछ सालों के दौरान दिल्ली मेट्रो का विस्तार भी हुआ है, लेकिन कोरोना वायरस के नियमों के चलते यात्रियों की संख्या पूर्व की तरह नहीं है। कभी दिल्ली मेट्रो की रोजाना कमाई 10 करोड़ के आसपास थी, लेकिन अब यह घटकर लाखों में आ गई है। इसके चलते दिल्ली मेट्रो रेल निगम 4000 करोड़ रुपये के घाटे में चल रही है। उस पर 7100 करोड़ रुपये डीएमआरसी को दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को देने हैं। ऐसे में यह कर्ज 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का हो गया है। दरअसल, दिल्ली मेट्रो के पास 14000 के आसपास कर्मचारी हैं। उनकी तनख्वाह के साथ दिल्ली मेट्रो के परिचालन पर भी एक निश्चित रकम खर्च होती है। ऐसे में कम मेट्रो यात्रियों की वजह से कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है।

तिहाड़ में कैदियों के बीच मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया मामला

नई दिल्ली। तिहाड़ जेल में मारपीट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। तिहाड़ परिसर स्थित महिला जेल में बुधवार सुबह कैदी व जेलकर्मी के बीच मारपीट का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि दोपहर में जेल संख्या आठ के भीतर दो कैदी आपस में भिड़ गए। इसके पहले कि मामला उग्र होता, दोनों कैदियों को काबू कर लिया गया। जिस कैदी को चोटें आई, उसे उपचार के लिए पहले जेल अस्पताल और फिर वहां से डीडीयू अस्पताल भेजा गया। हरिनगर थाना पुलिस ने घायल कैदी के बयान पर मामला दर्ज कर घटना की तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मामले की तहकीकात जारी है।

जिस कैदी ने शिकायत की है उसका नाम जावेद है। जावेद वार्ड संख्या तीन दो वर्ष नौ महीने से बंद है। बुधवार को दिन में तीन बजे जेल के एक सेवादार ने उसे एक रजिस्टर रखने के लिए दिया और बाहर निकल गया। जावेद ने पुलिस को बताया कि वार्ड संख्या तीन में ही बंद कैदी मनोज उसके पास आया और रजिस्टर मांगने लगा, लेकिन जावेद ने जब इंकार कर दिया तो गालियां देनी शुरू कर दी। जब जावेद ने गालियों पर आपत्ति जताई तो उसने मारपीट शुरू कर दी।

पीएम केयर्स फंड के कामकाज में केंद्र या राज्य सरकारों का नहीं कोई नियंत्रण

नई दिल्ली । पीएम केयर्स फंड के कामकाज में केंद्र या राज्य सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं है। यह सरकारी फंड नहीं है और पूरी पारदर्शिता के साथ काम करता है। इसके द्वारा एकत्र की गई राशि भारत के संचित कोष में नहीं जाती है और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के एक पैनल के चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा इसका आडिट किया जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में अवर सचिव प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने एक याचिका पर यह जानकारी दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ के समक्ष हलफनामा दाखिल करके दी। मामले में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी।

याचिकाकर्ता सम्यक गंगवाल ने संविधान के अनुच्छेद-12 के तहत पीएम-केयर्स फंड को सरकार की एक व्यवस्था घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पीएम-केयर्स फंड एक संवैधानिक पदाधिकारी के नाम से चलता है जो संविधान में निहित सिद्धांतों से बच नहीं सकता है और न ही वह संविधान से बाहर अनुबंध कर सकता है। उन्होंने पीएम-केयर्स फंड को एक सरकारी व्यवस्था के रूप में घोषित किया जाए। याचिका पर हलफनामा दाखिल कर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि पीएम केयर्स फंड की पारदर्शिता के लिए ट्रस्ट द्वारा प्राप्त किए गए अप्रयुक्त फंड की जानकारी के आडिटर की रिपोर्ट को आधिकारिक वेबसाइट पर डाला जाता है। उन्होंने कहा कि अगर याचिकाकर्ता केवल पारदर्शिता के लिए विभिन्न राहतों की मांग कर रहा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि संविधान के अनुच्छेद-12 के तहत पीएम केयर्स एक सरकारी व्यवस्था है या नहीं। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट को आनलाइन, चेक या डिमांड से दान मिलता है और प्राप्त किए गए धन का आडिट रिपोर्ट ट्रस्ट द्वारा किए गए खर्च के साथ वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है।

सार्वजनिक भलाई के सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रस्ट- उन्होंने कहा कि ट्रस्ट किसी भी अन्य धर्मार्थ ट्रस्ट की तरह बड़े सार्वजनिक हित में पारदर्शिता और सार्वजनिक भलाई के सिद्धांतों पर कार्य करता है। उन्होंने कहा कि मानद आधार पर पीएम केयर्स ट्रस्ट में अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं जो संविधान या संसद द्वारा नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का एक अधिकारी होने के बावजूद उन्हें मानद आधार पर ट्रस्ट में अपने कार्यों का निर्वहन करने की अनुमति है।

भारत के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे सहकारी संस्थाओं को संबोधित

नई दिल्ली,(एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को केंद्र में रखकर अस्तित्व में आये सहकारिता मंत्रालय के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह जी अपने तरह के पहले और अनूठे सहकारी समागम में सहकारिता से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे। सहकारिता सम्मेलन का आयोजन 25 सितम्बर को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने जा रहा है। इस मौके पर सहकारिता राज्य मंत्री बी. एल. वर्मा और इंटरनैशनल कोआपरेटिव एलांयस (ग्लोबल) के अध्यक्ष डॉ. एरियल ग्वार्को मौजूद रहेंगे। इस सम्मेलन में देश भर के लगभग 2000 से अधिक सहकारी बंधु एवं दुनिया भर से करोड़ों सहकारी जन कार्यक्रम में आभासी रूप से शामिल होंगे। देश में सहकारिता आंदोलन को मज़बूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढाँचा प्रदान करने, सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुँचाने वाले एक जन आधारित आंदोलन के रूप में मज़बूत करने में मदद करने एवं सहकारी समितियों के लिए 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और बहु-राज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम करने के लिए गठित सहकारिता मंत्रालय का मूल मंत्र है 'सहकार से समृद्धि'। प्रधानमंत्री मोदी जी के 'सबका साथ, सबका विकास' के स्वप्न को अमली जामा पहनाने हेतु सहकारिता मंत्रालय निश्चित रूप से अभूतपूर्व कार्य करेगा। सहकारिता सम्मेलन का आयोजन भारत की अग्रणी सहकारी संस्था इफको, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, अमूल, सहकार भारती, नैफेड, कृभको एवं समस्त सहकारी परिवार मिलकर कर रहा है।

रेडियल एंजियोप्लास्टी से डाक्टरों ने मरीज को घातक हार्ट अटैक से बचाया

नई दिल्ली । दिल्ली निवासी एक 25 वर्षीय अधिक वजन वाले पुरुष रोगी को रेडियल एंजियोप्लास्टी द्वारा एक घातक हार्ट अटैक से बचाया गया। दरअसल, रमन नामक एक युवक मैक्स अस्पताल साकेत की इमरजेंसी में सीने में दर्द की शिकायत लेकर आया था। जांच करने पर पता चला कि मरीज की बाई धमनी में 99 फीसद ब्लाकेज है।

मरीज का इलाज करने वाले डा. विवेका कुमार ने बताया कि यह प्रक्रिया जटिल इसलिए थी क्योंकि मरीज का वजन 100 किलो से ज्यादा था।उन्होंने बताया कि खून का बहाव ज्यादा न हो इसलिए रेडियल एंजियोप्लास्टी की प्रक्रिया अपनाई गई। जिससे ब्लाक कोरोनरी धमनियों को खोलकर रक्त के प्रवाह को फिर से शुरू किया जा सके। स्टेंट लगाने से डाक्टर मरीज की हालत को स्थिर करने में सफल रहे।

रेडियल एंजियोप्लास्टी के बाद बाई धमनी में सामान्य रक्त प्रवाह शुरू हो गया और मरीज की हालत में तेजी से सुधार हुआ। दो दिन अस्पताल में रहने के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। डा. के मुताबिक मरीज की कम उम्र को देखते हुए उसमें एक बायो डिसोल्वेबल स्टेंट लगाया गया है, जो दो साल के भीतर शरीर में घुल जाता है। इससे मरीज को जीवन भर ब्लड थिनर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है।

क्या है रेडियल एंजियोप्लास्टी

रेडियल एंजियोप्लास्टी प्रक्रिया में एक तार को ब्लाक कोरोनरी धमनी में ले जाया जाता है। फिर धमनियों में जहां ब्लाकेज होता है, उसके पार गुब्बारे नुमा स्टेंट को पहुंचाया जाता है, ताकि स्टेंट को धमनी में ट्यूब के रूप में खोला जा सके। साथ ही भविष्य में दोबारा धमनियों में आने वाली ब्लाकेज को रोका जा सके।

रेडियल एंजियोप्लास्टी चिकित्सकीय रूप से चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि ब्लाक धमनी तक रक्त हाथ की संकरी रक्त वाहिकाओं के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। इस प्रक्रिया से प्रमुख रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचने की संभावना कम होती है। इसके लिए विशेषज्ञ डाक्टरों की आवश्यकता पड़ती है। यह प्रक्रिया परंपरागत तरीकों के मुकाबले अधिक सुरक्षित मानी जाती है।

क्षेत्रीय कार्यालयों में एकीकृत शिविर आयोजित करने के निर्देश

नई दिल्ली,(प्रवीण कुमार सिंह)। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजय गोयल ने गुरुवार को बताया कि सभी क्षेत्रीय उपायुक्तों को स्वच्छता कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों के निवारण, करुणामूलक आधार पर नियुक्तियों के संबंध में प्रत्येक शनिवार को क्षेत्रीय कार्यालयों में एकीकृत शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन शिकायत निवारण शिविर के माध्यम से सफाई कर्मियों से संबंधित मुद्दों को हल करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस तरह की पहल से उनका मनोबल भी बढ़ेगा और वे अपने कर्तव्यों को अधिक कुशलता से निभाएंगे। संजय गोयल ने बताया कि सभी उपायुक्तों को हर शनिवार को नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर एकीकृत शिविर आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया है, जैसे कि रेहड़ी-पटरी वालों को नए एलओआर और सीओवी जारी करने, संपत्तियों की अस्थायी और स्थायी डी-सीलिंग की प्रक्रिया के संबंध में जहां डीएमसी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के लिए संपत्तियों को सील किया गया है व संपत्ति कर, कन्वर्जन शुल्क, पार्किंग शुल्क या किसी अन्य निगम के मुद्दों के संबंध में।

पराली के धुएं से राहत के लिए केंद्र ने संभाला मोर्चा, राज्यों को दिया सुझाव

नई दिल्ली। आम के आम, गुठलियों के भी दाम.. पराली के मामले में अब यही फार्मूला अपनाने की कोशिश है। लाख कोशिशों के बावजूद किसानों को पराली जलाने से रोकने में असमर्थता के बाद अब ऐसी राह निकालने की कोशिश हो रही है जिससे किसानों के लिए पराली नहीं जलाना फायदे का सौदा बने। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पर्यावरण मंत्रियों और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इसे लेकर एक अहम बैठक की।

पंजाब, हरियाणा सहित दिल्ली-एनसीआर के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने का सीजन 25 सितंबर से शुरू हो जाता है।राज्यों के साथ इस चर्चा में पराली को खेतों में जलाने से रोकने के लिए जिन विषयों पर मुख्य फोकस किया गया, उनमें कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की ओर से विकसित डी-कंपोजर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने, देशभर के पावर प्लांट्स में ईंधन के रूप में बायोमास का 10 फीसद तक इस्तेमाल करने, जिसमें पराली की मात्रा करीब 50 फीसद रखनी होगी, के साथ पशु चारे के रूप में इसके उपयोग को प्रोत्साहित करने व पराली को खेतों में खत्म करने के लिए किसानों को और मशीनें देने और पूर्व में दी गई मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।

यानी किसानों के लिए पराली आमदनी का साधन बने।भूपेंद्र यादव ने कहा कि पराली को खेतों में जलाने से रोकने के लिए राज्यों के साथ बेहतर चर्चा हुई है। सभी ने इसकी रोकथाम का भरोसा दिया है। हमारी कोशिश है कि इस बार पराली बिल्कुल भी न जले। इसके लिए कुछ अहम कदम उठाए गए हैं। देशभर के सभी पावर प्लांट्स को अब ईंधन के रूप में 10 फीसद बायोमास का इस्तेमाल करने को कहा गया है। पंजाब में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) ने इसे लेकर टेंडर निकाल दिए हैं। इसके साथ ही पशु चारे में भी पराली के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्यों से कहा गया है कि वे किसानों से इसे खरीदने की योजना बनाएं। अब तक गुजरात ने कच्छ क्षेत्र में पशु चारे के लिए इसकी मांग की है। जिसे किसानों से लेकर दिया जाएगा। इससे किसानों को भी फायदा होगा।

पर्यावरण सचिव आरपी गुप्ता ने बताया कि पावर प्लांट्स में बायोमास के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा मंत्रालय से बातचीत हो गई है, जो जल्द ही इसे लेकर गाइडलाइन जारी करेगा। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिस्सा लिया था, जो राज्य के पर्यावरण मंत्री भी हैं। साथ ही इस वर्चुअल बैठक में उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री दारा सिंह, राजस्थान के मंत्री सुखराम विश्नोई, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और पंजाब के प्रमुख सचिव पर्यावरण मौजूद थे। बैठक में दिल्ली-एनसीआर वायु गुणवत्ता आयोग के अध्यक्ष एमएम कुट्टी और पर्यावरण, कृषि व ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे। मालूम हो कि दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता के लिहाज से 25 सितंबर से 30 नवंबर तक का समय काफी अहम होता है। इस दौरान पंजाब, हरियाणा सहित पड़ोसी राज्यों में पराली जलाई जाती है।

साड़ी पहनकर रेस्तरां में एंट्री पर बवाल, महिला पर मैनेजर को थप्पड़ मारने का आरोप

नई दिल्ली । इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने वायरल हो रहा है. इसे वीडियो पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है. वीडियो में देखा जा सकत है कि एक महिला को साड़ी पहनने की वजह से दिल्ली के एक रेस्तरां में एंट्री नहीं मिली. हमारे देश में साड़ी को भारतीय परंपरा का प्रतीक माना जाता है. वीडियो में कहा जा रहा है कि महिला साड़ी पहनकर अंदर नहीं जा सकती.

सोशल मीडिया पर बवाल मचने से होटल प्रशासन ने बुधवार को बयान जारी कर, आरोपों को खंडन किया. रेस्तरां के आदिकारिक हैंडल ने इस मामले में कई वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किए और कहा कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो भ्रामक हैं क्योंकि ये एक घंटे में जो कुछ हुआ उसे केवल 10 सेकेंड दिखाता है. सेस्तरां के अधिकारियों ने महिला के मैनेजर को थप्पड़ मारने की सीसटीवी फुटेज भी ट्वीट की है.

सोशल मीडिया पर शुरू हुई बहस

वीडियो वायरल होने बाद सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बहस पैदा हो गई है कि साड़ी को रेस्तरां के लिए उपयुक्त क्यों नहीं माना जाता है. इस पर अधिकारियों ने कहा कि महिला को गेट पर इंतजार करने के लिए कहा गया था. क्योंकि उनका नाम रिजर्वेशन लिस्ट में नहीं था. इसके बाद महिला ने रेस्तरां में प्रवेश किया और कर्मचारियों को गाली देना शुरू कर दिया. अधिकारियों ने कहा कि इसके बाद जो सामने आया वो हमारी कल्पना से परे था. महिला ने हमारे मैनेजर को थप्पड़ मारा.

वीडियो 19 सितंबर को वायरल हुआ था. वीडियो में देखा जा सकताहै रेस्टोरेंट में कामर करने वाली कुछ महिलाएं साड़ी पहनने वाली मिहाल को रेस्टोरेंट के अंदर जाने से रोक रही हैं. इन महिलाओं का कहना है कि साड़ी 'स्मार्ट कैजुअल' ड्रेस कोड के तहत नहीं आथी है. इसलिए महिला अंदर नहीं जा सकती.

साड़ी पहनकर आने की अनुमति नहीं- घटना दक्षिणी दिल्ली के अंसल प्लाजा के एक रेस्टोरेंट बार की है. वीडियो में सुनाई दे रहा है कि महिला की एंट्री रोकी जाती है, तब वो रेस्टोरेंट के कर्मचारी को लिखित में देने के लिए कहती हैं. उनकी ओर से ये कहा जाता है कि आप लिख कर दें कि यहां साड़ी पहनकर आने की अनुमति नहीं है.

20 सितंबर को महिला ने वीडियो शेयर किया था. महिला ने फेसबुक पर लिखा इस वीडियो को ध्यान से सुनें क्योंकि दिल्ली के एक रेस्तरां में साड़ी एक स्मार्ट पोशाक नहीं है. महिला ने लिका होटल स्टाफ की तरफ से साड़ी के खिलाफ कई बहाने दिए गए लेकिन मुझे रेस्टोरेंट में बैठने नहीं दिया गया. क्योंकि हमारे देश की साड़ी को एक स्मार्ट आउटफिट नहीं माना जाता. उन्होंने कहा की साड़ी की वजह से जो मेरा अपमान हुआ है, वो अभी तक का सबसे बड़ा अपमान है और दिल दहला देने वाला है.

संपादकीय

ताकि बढ़े निवेश और रोजगार

स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाने की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जो कहा, उसमें कम शब्दों में एक बड़ी बात थी, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' यानी व्यापार करना आसान बनाना। यह सरकार कई साल से 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' पर काम कर रही है, और उन्होंने कहा भी कि देश के व्यापार और उद्योग आज इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं।

लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि इस तरह के सुधार सिर्फ सरकार तक सीमित न रहे, बल्कि ग्राम पंचायत और नगर निगमों, नगरपालिकाओं तक पहुंचे, इस पर देश की हर व्यवस्था को मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री की यह बात इसलिए ध्यान देने लायक है, क्योंकि इसमें यह अंतर्निहित है कि सरकार ने भले ही 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' कर दिया हो और बड़े उद्योगपतियों की जिंदगी आसान हो गई हो, लेकिन छोटे व्यापारियों व कारोबारियों को आज भी बहुत सारी रुकावटें झेलनी पड़ रही हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा बाधाएं उन लोगों के सामने हैं, जो नया काम शुरू करना चाहते हैं। पिछले साल लॉकडाउन लगने के कुछ ही समय बाद ऑल इंडिया मैन्युफैक्चर्स ऑर्गेनाइजेशन ने नौ और उद्योग संगठनों के साथ मिलकर एक देशव्यापी सर्वे किया था। इससे पता चला कि देश में एक तिहाई से ज्यादा छोटे और मध्यम उद्योग बंद होने के कगार पर हैं। व्यापारियों से बात कीजिए, तो उन सबका कहना है कि कोरोना के पहले झटके ने उनकी कमर तोड़ दी थी, जिसके बाद वे किसी तरह सब कुछ समेटकर अपने नुकसान का हिसाब जोड़ ही रहे थे कि दूसरी लहर आ गई। हालांकि, इन दो मुसीबतों के बाद भी आशा का दामन न छोड़ने वाले लोग हैं और उनका कहना है कि कम-से-कम अब वे हर हाल के लिए तैयार तो हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कभी भी फिर ऐसी हालत आ सकती है।

मैनेजमेंट के जानकारों का भी कहना है कि छोटे हों या बड़े, सभी व्यापारी अब यह सोचकर तैयारी कर रहे हैं कि कोरोना का अगला झटका आ गया, तो काम कैसे जारी रखा जाए। और ऐसा करने में उनके सामने जो दो सबसे बड़ी रुकावटें आती हैं, उनमें से एक है, मांग की कमी, और दूसरा, पैसे की कमी। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म 'फेसबुक' ने पिछले साल ओईसीडी और विश्व बैंक के साथ मिलकर भारत में छोटे और मंझोले कारोबारियों के बीच एक सर्वे किया था, जिसमें एक तिहाई लोगों ने आशंका जताई थी कि पैसे की व्यवस्था उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। पिछले ही हफ्ते फेसबुक ने ऐसे व्यापारियों को पांच से पचास लाख रुपये तक का लोन दिलवाने की मुहिम भी शुरू की है। हालांकि, इसका फायदा उन्हीं व्यापारियों को होगा, जो फेसबुक या उसके दूसरे एप इंस्टाग्राम, वाट्सएप पर छह महीने तक विज्ञापन दे चुके हों। सवाल यह है कि जिस तरह फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी छोटे व्यापारियों के लिए सहारा बनने की सोचती है, क्या देश में आने वाली दूसरी बड़ी कंपनियां भी ऐसा ही कर सकती हैं? यह सवाल इसलिए भी उठता है, क्योंकि पुराने वक्त से यह देखा गया है कि जब कहीं कोई बड़ा कारखाना लगता था, तो उसके आसपास बहुत से छोटे कारखाने, दुकानें, होटल, रेस्तरां, यानी करीब-करीब पूरा बाजार लग जाता था। ज्यादा बड़े उद्योग तो अपने आसपास पूरे-पूरे शहर ही बसा लेते थे। और, इसके साथ यह सवाल भी उठता है कि देश में कितने ऐसे बड़े उद्योग आ रहे हैं, जिनसे यह उम्मीद की जा सके?

यहां चीन की एक खबर पर नजर डालनी चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले हफ्ते अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं से कहा कि सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जिससे देश में संपत्ति का फिर से बंटवारा किया जा सके और सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो। चीनी समाचार एजेंसी के अनुसार, उन्होंने कहा कि बहुत ऊंची कमाई पर नियंत्रण लगाना और बहुत पैसा कमाने वाले लोगों व कंपनियों को प्रेरित करना होगा कि वे समाज को ज्यादा से ज्यादा वापस दें। इसका गरीबों को कितना फायदा होगा, यह अलग बहस का मुद्दा है, पर इतना तय है कि इसका अर्थ अमीरों पर ज्यादा टैक्स हो सकता है। ऐसा होने के बाद या ऐसा होने के डर से बहुत सी बड़ी कंपनियां फिर चीन से भागने लगेंगी। लेकिन जो कंपनियां चीन से भागेंगी, उनमें से कितनी भारत आएंगी? पिछले साल इसी महीने दावा किया गया था कि दो दर्जन बड़ी कंपनियां चीन छोड़कर भारत आ रही हैं और वे यहां डेढ़ अरब डॉलर का निवेश करेंगी। ये वे कंपनियां थीं, जो पहले ही चीन से निकलने का मन बना चुकी थीं और तब तक यह चिंता सामने आ चुकी थी कि उन्हें अपनी तरफ खींचने के मामले में भारत वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, बांग्लादेश और थाइलैंड जैसे देशों से पिछड़ चुका था। तब भी सरकार को उम्मीद थी कि जब ये कंपनियां आएंगी, तो 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और करीब 150 अरब डॉलर का उत्पादन भी होगा।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, साल 2020-21 में भारत में कुल 81.72 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। यह रकम इसके पिछले साल से 10 प्रतिशत ज्यादा है। लेकिन एक अमेरिकी रिसर्च ग्रुप का कहना है कि अगर भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है, तो उसे हर साल कम से कम 100 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाना होगा।

दूसरी बात, जो पैसा आ रहा है, उसमें से काफी कुछ वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी के रास्ते भी आ रहा है। इनमें से ज्यादातर टेक्नोलॉजी कंपनियों में जा रहा है, जहां जमीन पर बहुत कुछ नहीं होता। इसीलिए, इतना निवेश आने के बाद भी देश में ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या ऐसे कारोबार में निवेश, जिनमें जमीन पर आर्थिक गतिविधि हो, फैक्टरी लगे, बिल्डिंग बने, बहुत से लोगों को रोजगार मिले और जीडीपी में बढ़ोतरी हो, कम हो रहा है। सन 2011 से 21 के बीच ऐसा निवेश जीडीपी का 34.3 प्रतिशत रहा, लेकिन 2020-21 में यह सिर्फ 27.1 फीसदी रह गया है। ऐसे में, यह सवाल उठना लाजिमी है कि आंकड़ों में, सरकारी फाइलों में विदेशी निवेश कितना भी बढ़ता दिखे, क्या वह आम आदमी को रोजगार देने में मदद करेगा? और सरकार ऐसा क्या करेगी कि इस सवाल का जवाब हां में ही मिले? तभी आजादी का अमृत महोत्सव सबके लिए अमृतवर्षा का सबब बन पाएगा।

प्रवीण कुमार सिंह

कैसे पंजाब में कांग्रेस पार्टी अपने ही बुने जाल में उलझ गयी है

> **कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने बेहतरीन काम किया और मुझे ये विश्वास है की कभी-कभी परिवार में छोटे-मोटे मतभेद हो जाते हैं, पर मुझे ये विश्वास है कि वो अपनी परिपक्वता का परिचय देंगे और उनका आशीर्वाद जो उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को कल दिया है, कांग्रेस की सरकार पर और समर्थन पर इसी प्रकार बना रहेगा.÷ सुरजेवाला का यह कहना अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है. किसी को बेआबरू करके फिर उस नेता से आशीर्वाद और समर्थन की आस सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है. किसी नेता को किसी पद से हटाने का अधिकार पार्टी को होता है पर ऐसी फजीहत किसी और दल में नहीं होती.**

कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा कर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री तो बना दिया, पर पार्टी की मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं. पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने एक प्रश्न के उत्तर में रविवार को कह दिया कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा. कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव में मुख्यमंत्री पद के दावेदार नवजोत सिंह सिद्धू होंगे ना की चन्नी, जो सच से परे नहीं है. पर बाद में पार्टी को अपनी गलती का अहसास हुआ कि इस बयान से पार्टी की पोल खुल गयी कि चन्नी को सिर्फ दलित वोट जुटाने के लिए अस्थायी मुख्यमंत्री बनाया गया है और इससे पंजाब के दलित वोटर कांग्रेस पार्टी से नाराज़ हो सकते हैं, लिहाजा कांग्रेस पार्टी के 'विद्वान' और सुलझे हुए केंद्रीय नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं और पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता हैं, को सोमवार को स्थति स्पष्ट करनी पड़ी. सुरजेवाला ने स्थिति सुधारने के चक्कर में पार्टी को एक हास्यास्पद स्थिति में ला कर खड़ा कर दिया यह कह कर कि पार्टी मुख्यमंत्री चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी. अभी तक तो यह ही देखा और सुना था कि या तो कोई भी पार्टी चुनाव के पूर्व किसी नेता को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करती है या फिर किसी एक नेता को प्रोजेक्ट किया जाता है, जैसे कि 2017 के चुनाव में अमरिंदर सिंह थे, पर अब पार्टी एक मुख्यमंत्री पद के लिय दो दावेदारों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी. कहते हैं कि शेर की सवारी करने से ज्यादा मुश्किल होता है उस पर से उतरना. उतरते ही शेर आप पर हमला भी कर सकता है. ऐसा ही कुछ कांग्रेस पार्टी के साथ हो रहा है. जाति का कार्ड खेल तो दिया, यह सोच कर कि एक दलित सिख मुख्यमंत्री और

एक जट सिख प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव में सभी विरोधियों की छुट्टी हो जायेगी. पर अब कांगेस पार्टी की परेशानी है कि अगर चन्नी को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश नहीं किया गया तो दलित सिख नाराज़ हो जाएंगे और अगर जट सिख सिद्धू को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया तो जट सिख भड़क जाएंगे.

जट सिख वैसे ही अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद से पार्टी से नाराज़ हो सकते हैं. अगर सिद्धू को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया तो उनका वोट किसी और विरोधी पार्टी को चला जाएगा. इस लिए पार्टी के महान नेता राहुल गांधी और पार्टी के विद्वान प्रवक्ता सुरजेवाला अब संयुक्त दावेदारी की बात गोलमोल तरीके से करने लगे हैं. आने वाला समय ही बतायेगा कि क्या पंजाब के मतदाता उतने ही मुर्ख हैं जितना कि कांग्रेस पार्टी उन्हें साबित करने में तुली है या फिर कांग्रेस पार्टी अपने ही बुने जाल में फंस जाएगी?

कांगेस पार्टी की यह एकमात्र समस्या नहीं है. पार्टी ने वरिष्ट नेता अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटा तो दिया, क्योंकि वह दिल्ली दरबार में जी हुजूरी नहीं करते, पर अब पार्टी को यह चिंता सताने लगी है कि अमरिंदर सिंह कहीं कांग्रेस पार्टी का खेल ना बिगाड़ दें. अमरिंदर सिंह की लोकप्रियता में गिरावट जरूर आई थी, पर यह भी सच है कि अभी भी पंजाब में कांग्रेस पार्टी के वह सबसे बड़े और लोकप्रिय नेता हैं. सिद्धू और चन्नी को अगर मिला भी दें तो अमरिंदर सिंह के मुकाबले उनका वजन हलका ही रहेगा. शनिवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अमरिंदर सिंह ने यह स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी ने उनका अपमान किया है. पहले ही अमरिंद सिंह ने घोषणा की थी कि अभी उनका सक्रिय राजनीति से रिटायर होने का कोई इरादा नहीं है. सोमवर को चन्नी के शपथग्रहण समारोह, जिसमें पार्टी के बेताज बादशाह राहुल गांधी शामिल हुए, से अमरिंदर सिंह दूर रहे. अब कांग्रेस पार्टी को भय सताने लगा है कि कहीं अमरिंदर सिंह उनका खेल ना बिगड़ दें, जिस सम्भावना से अभी इनकार नहीं किया जा सकता है.

इतना तो स्पष्ट है कि अमरिंदर सिंह अकाली दल में शामिल नहीं होंगे. ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में वह 1984 में कांग्रेस पार्टी छोड़ कर अकाली दल में शामिल हो गए थे और 1992 में वह कांग्रेस पार्टी में वापस आये. पर इस बार अकाली दल से दूरी का कारण है कि अकाली दल सुखबीर सिंह बादल को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने का ऐलान कर चुकी है और अमरिंदर सिंह को अगर मुख्यमंत्री पद नहीं मिला तो वह अकाली दल में क्यों शामिल होंगे.

अमरिंदर सिंह के पास फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी में शामिल होने का विकल्प है. दोनों पार्टियों को मुख्यमंत्री पद के लिए किसी बड़े नेता की तलाश है और उन्हें सहर्ष अमरिंदर सिंह का स्वागत करने में परहेज नहीं होगा, क्योंकि वह जिस भी दल में शामिल होंगे उसकी ताकत बढ़ जायेगी. बीजेपी में भी शामिल होना थोडा मुश्किल लग रहा है क्योंकि अमरिंदर सिंह उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने कृषि कानूनों के विरोध में किसान आन्दोलन को बढ़ावा दिया था. जब तक बीजेपी कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक अमरिंदर सिंह बीजेपी से दूर ही रहेंगे और कृषि कानूनों के मुद्दे पर बीजेपी झुकने को तैयार नहीं है. एक बीच का रास्ता निकल सकता है कि बीजेपी कृषि कानून में कुछ संशोधन करने को तैयार हो जाए, जिस स्थिति में अमरिंदर सिंह उसका क्रेडिट ले कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं. अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी पंजाब चुनाव में एक बड़ी शक्ति बन जायेगी. आम आदमी पार्टी में शामिल होना भी एक विकल्प है, पर वहां भी समस्या कांग्रेस वाली ही है. राहुल गांधी की ही तरह आम आदमी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी दरबारी नेता ही भाते हैं. पार्टी से कम से कम दर्ज़न भर बड़े नेताओं को इसी कारण या तो पार्टी से निकाल दिया गया या फिर वह आम आदमी पार्टी से दूर हो गए. उम्र के इस पड़ाव में अमरिंदर सिंह जैसा बड़ा नेता केजरीवाल को अपना नेता नहीं मानेगे. अगर उन्हें ऐसा ही करना होता तो फिर राहुल गांधी उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाते ही नहीं.

अपनी स्वयं की पार्टी गठित करने का विकल्प अमरिंदर सिंह के सामने है. समय कम है, पर यह संभव है. अगर उन्होंने ऐसा किया तो कांग्रेस पार्टी से नाराज़ कई दूसरे राज्यों के अन्य नेता भी अमरिंदर सिंह के साथ जुड़ सकते हैं. हताश और परेशान कांग्रेस पार्टी अब इसी प्रयास में जुटी है कि अमरिंदर सिंह कुछ ऐसा कदम नहीं उठाए जिससे पंजाब में पार्टी का टायर पंचर हो जाए. कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने बेहतरीन काम किया और मुझे ये विश्वास है की कभी-कभी परिवार में छोटे-मोटे मतभेद हो जाते हैं, पर मुझे ये विश्वास है कि वो अपनी परिपक्वता का परिचय देंगे और उनका आशीर्वाद जो उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को कल दिया है, कांग्रेस की सरकार पर और समर्थन पर इसी प्रकार बना रहेगा. सुरजेवाला का यह कहना अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है. किसी को बेआबरू करके फिर उस नेता से आशीर्वाद और समर्थन की आस सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है. किसी नेता को किसी पद से हटाने का अधिकार पार्टी को होता है पर ऐसी फजीहत किसी और दल में नहीं होती. कांग्रेस पार्टी अमरिंदर सिंह से परिपक्वता की उम्मीद कर रही है, जिस परिपक्वता का परिचय खुद कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया. अगर कांग्रेस पार्टी के अपरिपक्व नेताओं ने परिपक्वता दिखाई होती तो अब तक पंजाब में समस्या उलझने की जगह सुलझ चुकी होती.

दुनिया की दृष्टि बदलने वाले स्वामी विवेकानंद, शिकागो में बजाया था भारतीय धर्म-संस्कृति का डंका

समकालीन विश्व इतिहास में 11 सितंबर 1893 का दिन एक युगांतकारी परिघटना का पड़ाव बना था। उस दिन शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन के मंच से स्वामी विवेकानंद ने भारतीय धर्म-संस्कृति का ऐसा शंखनाद किया कि सुनने वाले सम्मोहित होकर रह गए। उन श्रोताओं में जर्मन भाषाविद् और प्राच्य विद्या के मर्मज्ञ प्रोफेसर फ्रेडरिक मैक्समूलर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे मूर्धन्य विज्ञानी भी थे। स्वामी जी के विचार सुनकर भारत को देखने की पश्चिमी विद्वानों की दृष्टि ही बदल गई कि जिसे वे जादू-टोना और सपेरों का देश समझते रहे, वह तो ज्ञान-विज्ञान, दर्शन और साहित्य की अविरल धारा को समेटे है। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि, 'संसार भारत माता का अपार ऋणी है। यदि हम विश्व के सभी राष्ट्रों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो पाते हैं कि विश्व में ऐसी कोई जाति नहीं है, जिसका संसार उतना ऋणी है, जितना वह हमारे भद्र हिंदू पूर्वजों का है।'पश्चिमी जगत पर स्वामी विवेकानंद का ऐसा असर हुआ कि हिंदुत्व के विविध आयामों पर व्याख्यान के लिए उन्हें जगह-जगह आमंत्रित किया जाने लगा। इसी कड़ी में मैक्समूलर ने स्वामी जी को अपने यहां भोजन पर आमंत्रित किया। यह 28 मई 1896 की तिथि थी। मैक्समूलर से घंटों शास्त्रर्थ हुआ। मैक्समूलर से मिलकर स्वामी जी भी अभिभूत हुए। इस मुलाकात पर अपने संस्मरण में उन्होंने लिखा कि जैसे वह प्राचीन भारत के किसी महान ऋषि के समक्ष बैठे हैं। उन्हें लगा कि ऋषि वशिष्ठ और अरुंधती ईश्वर प्राणिधान में मग्न हैं। विवेकानंद और मैक्समूलर का यह मिलन महज दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था। यह संगम उन पूर्वाग्रहों का पराभव था, जो रुडयार्ड किपलिंग जैसों की दृष्टि में कभी संभव नहीं था, क्योंकि वह पश्चिम को सदैव पूरब से श्रेष्ठ मानते रहे। इस प्रकार विवेकानंद और मैक्समूलर का मिलन वास्तव में पूरब और पश्चिम का सेतुबंधन था।

प्रो. यूजेन वर्नोफ 19वीं सदी के मध्य यूरोप में प्राच्यविद्या के प्रतिष्ठित आचार्य रहे। वर्नोफ ने ही मैक्समूलर को संस्कृत पढ़ाई तथा उन्हें वैदिक वांग्मय पर गहन शोध के लिए प्रेरित किया। मैक्समूलर ने तीन दशक से भी अधिक समय वेदों पर अध्ययन और शोध किया। जब उनका भाष्य प्रकाशित हुआ तो यूरोप, अमेरिका और भारत का विद्वत वर्ग चमत्कृत हो उठा। यह पश्चिम में वैदिक ज्ञान की 'दिग्विजय यात्र' थी। यह संपूर्ण यूरोप में वैदिक ज्ञान के प्रति आए पुनर्जागरण का उत्कर्ष था। मैक्समूलर वैदिक ज्ञान के उपासक तथा अनन्य भारत प्रेमी थे। भारत से बाहर जन्म लेकर मां भारती की महती सेवा करने वाले महान मनीषी थे। उनकी मेधा से प्रभावित राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने यथार्थ ही कहा था कि महर्षि सायण की आत्मा ही जर्मनी में मैक्समूलर के रूप में अवतरित हुई, क्योंकि समकालीन युग में वह वेदों के महानतम भाष्यकार हैं। मैक्समूलर का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने तुलनात्मक भाषाविज्ञान तथा धर्मो के तुलनात्मक अध्ययन की परंपरा शुरू की। भारत और भारतीय संस्कृति से उनके अनुराग की अभिव्यक्ति इन्हीं शब्दों में समझी जा सकती है, 'भारत आधुनिक विश्व का आध्यात्मिक पूर्वज है और जिस देश ने राम और कृष्ण को जन्म दिया, उसे गुलाम बनाना महापाप है।' मैक्समूलर ने भारत को कई प्रकार से गौरवान्वित किया। उन्होंने भारतीय साहित्य, दर्शन, धर्मग्रंथों की 50 से अधिक खंडों में ग्रंथमाला प्रकाशित की। 'इंडिया-व्हाट इट कैन टीच अस' नामक पुस्तक में वह बताते हैं कि विश्व भारतवर्ष से क्या-क्या सीख सकता है?

वैदिक ज्ञान का आज संपूर्ण विश्व पर बहुआयामी प्रभाव पड़ा है। आधुनिक जीवन का शायद ही कोई आयाम हो जिसमें भारतवर्ष ने योगदान नहीं किया। वस्तुतः तुलनात्मक भाषाविज्ञान के अध्ययन से जो तथ्य स्थापित हुए, उनसे पूर्वाग्रही यूरोपीय विद्वानों की जड़ता समाप्त हुई। ये यही मानते थे कि फलस्तीन और यूनान से प्राचीन कोई देश नहीं और हिब्रू से प्राचीन कोई भाषा नहीं है। बाइबल के अनुसार सृष्टि 4000 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। इस स्थापना के आलोक में वेदों के काल-निर्णय में यूरोपीय विद्वानों को बड़ी कठिनाई हुई, जो उन्हें ईसा से 2000 वर्ष पूर्व से आगे ले जाने के लिए किसी भी हाल में तैयार नहीं थे। हालांकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोदाई से उनके भ्रम टूटे और वे यह मानने को बाध्य हुए कि सृष्टि का इतिहास 4000 वर्ष से बहुत पुराना है।

यह मैक्समूलर ही थे जिन्होंने स्थापित किया कि हिब्रू नहीं, अपितु संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है और यूनानी या यहूदी नहीं, बल्कि हिंदू विश्व की प्राचीनतम जाति हैं। मैक्समूलर ने पाणिनी को विश्व का महानतम व्याकरणाचार्य घोषित किया। उनके अनुसार देववाणी संस्कृत अपनी समृद्ध शब्दावली तथा सर्वाधिक विज्ञानसम्मत व्याकरण से अलंकृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसमें प्राचीन हिंदू ग्रंथों का प्रणयन हुआ। संस्कृत गणित, विज्ञान, खगोल विज्ञान और आयुर्विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों की भाषा भी है। सर विलियम जोंस जैसे विद्वान भी इससे सहमति व्यक्त करते हुए कहते हैं, 'संस्कृत विश्व की सर्वाधिक पूर्ण भाषा है। यूनानी से भी अधिक परिपूर्ण तथा लैटिन से भी अधिक समृद्ध। यह भारत और उसकी संस्कृति के प्रति आकर्षण ही रहा कि उसने मैक्समूलर जैसे कई विद्वानों को प्रभावित किया। यह श्रृंखला बहुत लंबी है, जिनमें से तमाम यह मानते हैं कि गणित और विज्ञान हमने भारत से ही सीखा है।

तेजी से बढ़ती असमानता

नैशनल सैंपल सर्वे द्वारा करवाए गए ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे 2019 की रिपोर्ट ने एक बार फिर देश में लगातार बढ़ती गैर-बराबरी की ओर ध्यान खींचा है। रिपोर्ट के मुताबिक, देश की कुल संपत्ति का आधे से अधिक हिस्सा ऊपर की दस फीसदी आबादी के हाथों में सिमट गया है। निचले हिस्से की 50 फीसदी आबादी के पास महज दस फीसदी संपत्ति है। गांवों के मुकाबले शहरों में यह विभाजन और तीखा नजर आता है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अमीर दस फीसदी लोगों के पास 50.8 फीसदी संपत्ति है वहीं शहरी क्षेत्रों में यह 55.7 प्रतिशत पाया गया है।

इस विस्तृत सर्वे रिपोर्ट के अलग-अलग कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिन पर बारीकी से विचार होना चाहिए, लेकिन एक तथ्य स्पष्ट है कि विकास की प्रक्रिया जिन इलाकों में ज्यादा तेज रही, वहां असमानता का अनुपात भी ज्यादा है। इस तथ्य के अपने गहरे निहितार्थ भले हों, लेकिन यह अपने आप में कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी समय-समय पर आने वाली अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में यह तथ्य उजागर होता रहा है कि भारत में विकास की गति तेज होने के बाद भी पिछले ढाई-तीन दशकों में विषमता में तेज बढ़ोतरी हुई है।

क्रेडिट सुईस की ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2018 में तो कहा गया था कि देश की सबसे अमीर एक फीसदी आबादी के पास 51.5 फीसदी संपत्ति इकट्ठा हो गई है। ऐसी अलग-अलग रिपोर्टों में प्रतिशत का थोड़ा-बहुत अंतर कभी-कभार दिखता है तो उसकी एक वजह यह होती है कि उनमें संपत्ति की गणना के पैमाने अलग-अलग होते हैं। लेकिन इस तथ्य की पुष्टि इन तमाम रिपोर्टों से होती है कि भारतीय समाज में विषमता सुरसा के मुंह की तरह लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे यह रुझान अपने देश तक सीमित नहीं है। किसी भी समाज में अगर तेजी से समृद्धि आती है तो यह संभावना रहती है कि शुरू में संपत्ति आबादी के कुछ खास हिस्सों के हाथों में आए, जिससे विषमता बढ़ी हुई दिखने लगे। अपेक्षा यह रहती है कि बाद के दौर में यह धीरे-धीरे समाज के अन्य तबकों तक पहुंच कर उनके जीवन स्तर को भी ऊंचा करेगी। इसी बिंदु पर योजनाओं की भूमिका अहम हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना होता है कि अपनी स्वाभाविक गति में यह समृद्धि समाज के अन्य तबकों तक पहुंच रही है या नहीं। अगर नहीं पहुंचती है तो यह देखना होता है कि उसकी गति को बाधित करने वाले कारक कौन से हैं और उन्हें दूर करने के क्या इंतजाम हो सकते हैं। एनएसएस के ताजा आंकड़े बताते हैं कि अपने देश में सरकार को ऐसे इंतजामों पर खास ध्यान देने की जरूरत है।

आंकड़े बता रहे हैं कि किसानों की दशा पिछले 7 सालों में लगातार बेहतर हुई है

> **किसान संगठनों के धरनों से परेशान हो रहे लोगों के सामने बेबस होकर रह जाने के अलावा और कोई उपाय नहीं, क्योंकि कोई भी उनकी नहीं सुन रहा- न पुलिस, न सरकारें और न ही अदालतें। पुलिस और सरकारों की मजबूरी समझ आती है, लेकिन आखिर अदालतों को किसका भय है? क्या वे भी किसान संगठनों की मनमानी के आगे असहाय हैं? पता नहीं सच क्या है, लेकिन जब आम आदमी इस तरह परेशान होता है तो वह केवल कुढ़ता ही नहीं है, बल्कि व्यवस्था के विभिन्न अंगों पर उसका भरोसा भी कम होता है और जब ऐसा होता है तो लोकतंत्र कमजोर होता है।**

देश में कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन तेज है. बताया जा रहा है कि इन कृषि कानूनों से किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है. इसके साथ ही साथ यह भी साबित करने की कोशिश होती है कि किसानों की हालत बहुत खराब हुई है. हालांकि जब हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो स्थिति कुछ और ही नजर आती है. किसानों की आय में पिछले 9 सालों में करीब 59 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है. इसके साथ ही फसलों का बीमा कराने वाले किसानों की संख्या में भी जबरदस्त उछाल आया है. इसी तरह कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या में भी गिरावट आई है.

हिंदुस्तान टाइम्स में छपे एक साक्षात्कार में केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल के अनुसार सिचुएशन एसेसमेंट सर्वे बताता है कि किसानों की आय में 59 फ़ीसदी की वृद्धि हुई है. 2019 में हुए एक सर्वे के अनुसार किसानों की मौजूदा आय 10,218 रुपए दर्ज की गई जो 2012-13 के सर्वेक्षण से, जिसमें मासिक आय 6,426 रुपये थी की तुलना में कहीं ज्यादा है. इस सर्वे में यह भी दावा किया गया है कि मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किसानों की आय में जिसे अर्थशास्त्री वास्तविका कहते हैं, में लगभग 2 फ़ीसदी की वृद्धि दर्ज हुई है. हालांकि इस इनकम में केवल कृषि से होने वाले आय को ही नहीं जोड़ा गया है, बल्कि भूमि जोत और पशुधन से होने वाले आय को भी जोड़कर यह आंकड़े जारी किए गए हैं. दरअसल सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की भूमि और पशुधन और कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन करते हुए एक सर्वे किया है. हालांकि इससे पहले कृषि परिवारों की भूमि और पशुधन होल्डिंग सर्वेक्षण और सेचुएशन असेसमेंट सर्वे के अलग-अलग सर्वे किए जाते थे और उनके अलग-अलग आंकड़े जारी किए जाते थे. लेकिन इस बार यह दोनों एक साथ हुए हैं.

ऑल इंडिया लेवल पर 2018-19 के दौरान हर कृषि परिवार की औसत मासिक आय 10,218 रुपए थी. इस कुल औसत आय में मजदूरी से 4,063 रुपए, खेती या फसल उत्पादन से 3798 रुपए, जानवरों से 1582 रुपए, गैर कृषि व्यवसाय से 6041 रुपए और भूमि को पट्टे पर देने से 134 रुपए होती है. यानि कि कृषि परिवारों में आने वाली कुल आय का 39.8 फ़ीसदी इनकम मजदूरी से अर्जित होता है. वहीं खेती और फसल उत्पादन से कुल आय का 37.2 फ़ीसदी अर्जित होता है. पशुओं से 15.5 फ़ीसदी और गैर कृषि व्यवसाय से 6.3 फ़ीसदी किसान परिवारों को इनकम होती है. इस सर्वे की सबसे खास बात है कि इसमें गैर कृषि मजदूर भी शामिल हैं.

कृषि से कमाई करने वालों की तादाद बढ़ी है

आंकड़ों पर नजर डालें तो हमें समझ में आएगा की ग्रामीण इलाकों में उन परिवारों की संख्या जिनकी प्राथमिक आय कृषि से आती है, साल 2013 से 2019 में बढ़ी है. साल 2013 में इन परिवारों की संख्या जहां 54 फ़ीसदी थी वहीं 2019 में यह बढ़कर 58 फ़ीसदी हो गई. वहीं 2013 और 2019 के बीच कृषि परिवारों के आय की तुलना करें तो इसमें भी 59 फ़ीसदी की वृद्धि दर्ज हुई है. वहीं अगर फसल उत्पादन से आय की वृद्धि से पर नजर डालें तो 2013 से 2019 के बीच यहां 1 से 15 फ़ीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है. वहीं पशुपालन से आय में 27 से 34 फ़ीसदी की वृद्धि हुई है.

पहले के मुकाबले आज के किसान अधिक मात्रा में अपनी फसलों का बीमा करा रहे हैं. जुलाई से दिसंबर के दौरान के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि इस समयावधि में 8.3 फीसद कृषि परिवारों ने धान का बीमा कराया था. वहीं अगर 2012-13 के इसी समयावधि पर नजर डालें तो बीमा कराने वाले किसान परिवारों संख्या 4.8 फीसदी थी. इसी तरह इसी समयावधि में सोयाबीन की फसल का बीमा 27.5 परसेंट जबकि 2012-13 में 14 परसेंट और कपास में 25.4 परसेंट ने बीमा कराया जबकि 2012-13 में केवल 10.4 परसेंट ने बीमा कराया था. इसका सीधा मतलब यही निकल रहा है कि इन सात सालों में किसान की स्थित सुधरी है.

किसानों के कर्ज की क्या स्थिति भी सुधरी है

2013 के आंकड़ों से अगर 2019 के आंकड़ों से तुलना करने पर पता चलता है कि 2013 में जहां कुल 52 परसेंट किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे वहीं 2019 में ये घटकर 50 परसेंट हो गई है. पर ऐसा नहीं है कि किसानों ने कर्ज लेना ही छोड़ दिया है. किसानों की आय में वृद्धि के साथ-साथ कर्ज में बढ़ोतरी भी हुई है. इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट पर नजर डालें तो 2013 से 2019 के बीच किसानों के कर्ज में लगभग 58 फ़ीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इस रिपोर्ट के मुताबिक 2003 में किसानों के वार्षिक औसत आय 25,380 रुपए थी. जबकि उस पर कर्ज 12,585 रुपए था. वहीं 2013 में आए 77,112 रुपए और उस पर कर्ज 47,000 का था. लेकिन 2019 में जब आय बढ़कर 1,00,044 हुई तो कर्ज का बोझ भी बढ़कर 74,121 रुपए हो गया. यानि 2003 से 2019 तक जहां आय में 4 गुना की वृद्धि हुई है. वहीं कर्ज में 6 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. मतलब कर्ज में बढ़ोतरी हुई है पर कर्ज के तले दबे किसानों की संख्या में गिरावट हुई है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि आंध्र प्रदेश के किसानों पर सबसे ज्यादा लोन है. वहीं देश के 3 राज्यों (आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब) में प्रत्येक किसान परिवार पर औसतन 2 लाख से अधिक का कर्ज है. और पांच राज्यों (हरियाणा, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु) में यह आंकड़ा एक लाख के पार चला जाता है.

बजट की वजह से भी बढ़ी है किसानों की आय

किसानों की आय वृद्धि में बजट आवंटन का भी खास योगदान है. अगर हम 2013-14 में कृषि विभाग के लिए आवंटित बजट को देखें तो वह 21,933.50 लाख करोड़ रुपए थी. जो 2021-22 में लगभग 5.5 गुना से अधिक बढ़ाकर 1,23,017.57 करोड़ कर दिया गया है. यही नहीं अगर हम बीते 6 वर्षों में कृषि के लिए थोक मूल्य सूचकांक पर नजर डालें तो यह 111 से बढ़कर 134 हो गया है. वहीं गैर कृषि के लिए थोक मूल्य सूचकांक भी 106 से बढ़कर 116 हो गया है. इसके साथ ही पीएम किसान योजना के तहत अब तक 11.37 करोड़ किसान परिवारों को उनके बैंक खातों में सीधे 1.58 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है.

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91
से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह, टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

रायपुर में वार्ड की सफाई करने कम संख्या में पहुंचे कामगार, ठेकेदारों पर 10-10 हजार का जुर्माना

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बुधवार को दो वार्डों में निर्धारित से कम संख्या में नगर निगम रायपुर के अनुबंधित सफाई ठेका कामगार ड्यूटी पर पहुंचे। इस बात की जानकारी मिलते ही जोन 5 के पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 41 और महंत लक्ष्मीनारायण दास वार्ड नंबर 43 के क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का प्रत्यक्ष अवलोकन करने सहायक स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर तृप्ति पाणीग्रही पहुंचीं।इस दौरान ठेका सफाई कामगारों की उपस्थिति का निरीक्षण किया। दोनों वार्ड क्रमांक 41 और 43 में निर्धारित 40 सफाई कामगार से कम संख्या में ठेका सफाई कामगार कार्य पर उपस्थित मिले। इस पर सहायक स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर पाणीग्रही ने जोन स्वास्थ्य अधिकारी भूषण ठाकुर, जोन स्वच्छता निरीक्षक दिलीप साहू को तत्काल वार्ड नंबर 41 के सफाई ठेकेदार अनिल गिलारे और वार्ड नंबर 43 के सफाई ठेकेदार मेसर्स आदित्य इंटरप्राइजेस को नोटिस भेजकर उन दोनों सफाई ठेकेदारों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सहायक स्वास्थ्य अधिकारी ने निर्धारित संख्या में ठेका सफाई कामगारों की शत- प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करवाने के निर्देश जोन स्वास्थ्य अधिकारी, जोन स्वच्छता निरीक्षक को वार्ड क्रमांक 41 और 43 के सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान स्थल पर दिए हैं। गौरतलब है कि शहर की साफ सफाई में ड्यूटी लगने के बाद भी सफाईकर्मी मौके से गायब रहते हैं।इसकी लगातार शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष नागभूषण राव ने वार्डों में बुधवार से औचक निरीक्षण के निर्देश दिए है। पहले दिन वे भी वार्ड में स्वास्थ्य अधिकारी विजय पांडेय के साथ जाने वाले थे, लेकिन अचानक विजय पांडेय की तबियत खराब हो जाने के कारण अब गुरुवार से दौरा करेंगे।

यूनिवर्सिटी में सेंट्रल लाइब्रेरी का निरीक्षण करेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, तैयारियों में जुटा प्रशासन

मेरठ । प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस महीने के अंत तक मेरठ भ्रमण कर सकती हैं। सूत्रों की मानें तो राज्यपाल के आने की अभी तिथि तय नहीं है, मगर माना जा रहा है कि 27, 28 सितंबर को दो दिवसीय कार्यक्रम राज्यपाल का मेरठ में रहेगा। विवि में काफी समय तक राज्यपाल ठहरेंगी, जहां वह विवि प्रशासन संग शोध कार्य समेत परिसर स्थित अन्य महाविद्यालयों का भ्रमण कर सकती हैं। इसके लिए विवि प्रशासन ने कमर कस ली है। जिसके तहत राज्यपाल के आगमन की तैयारियां शुरू कर दी हैं।
हालांकि अभी नहीं मिला कार्यक्रम-सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल के आगमन की तिथि और विवि के कार्यक्रम की सूची और समय का प्रोग्राम अभी विवि प्रशासन को मिला नहीं आया है। आज गुरुवार को कुलपति डा. आरके मित्तल फोन पर लखनऊ स्थित राजभवन के अधिकारियों से बात कर कार्यक्रम की जानकारी हासिल करेंगे। मगर, उससे पहले ही विवि प्रशासन शुरूआती तैयारियों में जुट गया है।
कराई जा रही सफाई-राज्यपाल सबसे पहले विवि के मुख्य गेट पर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन करेंगी। उसके बाद राज्यपाल का काफिला सेंट्रल लाइब्रेरी पहुंच सकता है। यह सेंट्रल लाइब्रेरी करोड़ों रुपये कीमत में तैयार हुई थी। इस लाइब्रेरी का पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उदघाटन किया था। इसी को ध्यान में रखते हुए सरदार पटेल की प्रतिमा और उसके आसपास की सफाई कराई जा रही है। वहीं सेंट्रल लाइब्रेरी समेत सेमिनार हाल में भी साफ-सफाई का कार्य चल रहा है।

पटना में तेजस्वी यादव व मीसा भारती पर पांच करोड़ की ठगी की एफआइआर, पैसे लेकर टिकट नहीं देने का आरोप

पटना । बिहार के पटना से यह बड़ी खबर है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे व बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी

यादव तथा उनकी बहन व राज्यसभा सदस्य मीसा भारती पर पटना के कोतवाली थाना में ठगी का मुकदमा दर्ज किया गया है। उनपर बीते लोकसभा चुनाव में पैसे लेकर टिकट नहीं देने का आरोप लगाया गया है।
लोकसभा चुनाव में टिकट के नाम पर ठगी का आरोप-ज्ञात हो कि कांग्रेस नेता व अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में 18 अगस्त को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव व मीसा भारती तथा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश तथा राजेश राठौर सहित कुल छह लोगों को आरोपित बनाया गया। संजीव कुमार सिंह ने उनपर बीते लोकसभा चुनाव में पैसे लेकर टिकट न देने का आरोप लगाया है। कहा है कि टिकट देने के नाम पर पांच करोड़ की ठगी की गई है। कांग्रेस नेता संजीव कुमार सिंह ने मुकदमे में आरोप लगाया है कि आरजेडी में उनसे लोकसभा चुनाव का टिकट देने के नाम पर पांच करोड़ रुपये ठग लिए गए। टिकट भी नहीं दिया गया। फिर, बाद में विधानसभा चुनाव का टिकट देने का गलत आश्वासन दिया गया। संजीव का आरोप है कि उन्होंने टिकट के लिए आरजेडी कार्यालय में तेजस्वी यादव और मदन मोहन झा को पांच करोड़ रुपये दिए थे। बाद में टिकट नहीं मिलने पर रुपये वापस मांगने पर तेजस्वी यादव ने हत्या की धमकी दी थी।
कोर्ट के आदेश पर कोतवाली थाना में एफआइआर दर्ज- संजीव कुमार सिंह के मुकदमे में सीजेएम कोर्ट ने 16 सितंबर को पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा के माध्यम से कोतवाली थाना को एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद बुधवार को यह एफआइआर दर्ज कर ली गई है।, **तेजस्वी यादव ने सफाई में कही ये बातें**- इस मामले में तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो तो सब साफ हो जाएगा। आरोप लगाने वाले से यह भी पूछना जरूरी है कि उसके पास पांच करोड़ रुपये कहां से आए। कानून अपना काम करेगा।

बंदरगाह पर हेरोइन बरामदगी देश की सुरक्षा के लिए खतरे का आगाज, बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी

प्रयागराज । वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने गुजरात के उद्योगपति के निजी नियंत्रण वाले बंदरगाह से अरबों रुपये कीमत के ड्रग्स हेरोइन की बरामदगी को देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा ठहराया है। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर अडानी के नियंत्रण के पोर्ट पर दो कंटेनर में रखी 22 हजार करोड़ की हेरोइन और अफीम पकड़ी गई है। ऐसी आशंका है कि इसके पहले भी हेरोइन का यह अवैध कारोबार लगातार भारत मे संचालित होता आ रहा था। उन्होंने कहा कि यह मसला गंभीर है और भारत सरकार को इस पर निजी संबंध से आगे उठकर देश की सुरक्षा के प्रति चौकन्नी नजर से देखते हुए कदम उठाने चाहिए।
पाकिस्तान की साजिश हो सकती है यह- प्रमोद तिवारी ने प्रतापगढ़ में पत्रकारों से कहा कि ड्रग्स की बड़े पैमाने पर यह बरामदगी भारतीय युवाओं के स्वास्थ्य के लिए उड़ता हिन्दुस्तान बनाने का पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की गहरी खतरनाक साजिश का हिस्सा है। इस बंदरगाह के पाकिस्तान से बहुत करीब होने के कारण सामरिक दृष्टिकोण से भारत देश की सुरक्षा के लिए भी यह एक बड़े गंभीर खतरे का आगाज है। उन्होंने कहा कि हमें यह याद रखना चाहिए कि 26/11 मे जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था तो उस समय कसाब समेत दस आतंकवादी गुजरात के समुद्र तट से मुंबई में प्रवेश किए थे।
क्या व्यक्तिगत संबंध राष्ट्रहित से ज्यादा बड़ा है- प्रमोद तिवारी ने यह भी सवाल उठाया कि लखनऊ और मुंबई सहित देश के कई एयरपोर्ट अडानी को दिए गए हैं। क्या भाजपा बताएगी कि उसका व्यक्तिगत संबंध राष्ट्रहित से ज्यादा बड़ा है। उन्होंने सरकार से कहा है कि वह देश को बताएं कि करोड़ो की ड्रग्स बरामदगी के बाद भी अडानी आज बाहर कैसे हैं। केंद्र सरकार अडानी के खिलाफ तत्काल मुकदमा कायम कर इसकी निष्पक्ष जांच हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच की निगरानी में सीबीआई से कराए।

सीएम योगी ने किया पीएम मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन

लखनऊ । भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड में है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान की अगुआई में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर एक टीम बनाई है। धर्मेन्द्र प्रधान के साथ केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बुधवार से लखनऊ में हैं। कल पहले चरण की चुनावी बैठक के गुरुवार को भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उनके साथ धर्मेन्द्र प्रधान व अनुराग ठाकुर तथा भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पीएम नरेन्द्र मोदी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर आधारित इस प्रदर्शनी का सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ धर्मेन्द्र प्रधान व अनुराग ठाकुर ने अवलोकन किया।

सीएम योगी आदित्यनाथ की यहां पर मौजूदगी में आज ही भाजपा चुनावी संगठन की बैठक होगी। जिसके बाद सभी प्रभारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में भाजपा चुनावी संगठन की बैठक में सभी प्रभारियों के काम का बंटवारा किया जाएगा। चुनाव प्रभारी गण गुरुवार को एक बार फिर से मंथन में लगे हैं।

उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अपनी चुनाव तैयारियों को लेकर बैठक शुरू कर दी है। भाजपा के चुनाव प्रभारी और केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बुधवार को लखनऊ पहुंचकर भाजपा कार्यालय में संगठन के पदाधिकारियों, डिप्टी सीएम और अन्य मंत्रियों के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान बैठक में मौजूद थे।

भारतीय जनता पार्टी के प्रभारियों ने विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव में क्षेत्र के प्रभारियों के साथ बैठक की। संगठनात्मक बैठक में पीएम नरेन्द्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की योजनाओं और उन पर चर्चा की गई। बुधवार को परिचय बैठक थी। इस बैठक के बारे में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया कि भाजपा संगठनात्मक पार्टी है और बूथ लेवल तक इसमें हमारे कार्यकर्ताओं का गठन है। यही विशेषता पूरे भारत में है। भाजपा के हर व्यक्ति को अपना दायित्व पता है कि किस कार्यकर्ता को क्या करना है। अब सरकार के अच्छे कामों को जनता तक पहुंचाएं यह संगठन का काम है।

पाटी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, चुनाव प्रभारी व केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान व विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में केन्द्रीय मंत्री व प्रदेश चुनाव सहप्रभारी अनुराग ठाकुर, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डा. दिनेश शर्मा, केन्द्रीय मंत्री व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य, प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल सहित प्रदेश के सभी चुनाव सहप्रभारी केन्द्र सरकार में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे मंत्रिगण व उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट व राज्यमंत्रियो सहित प्रदेश सहमहामंत्री संगठन कर्मवीर, प्रदेश महामंत्री व क्षेत्रीय अध्यक्ष सम्मिलित हुए।

बैठक में प्रदेश चुनाव सह प्रभारी व केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, सुश्री सरोज पाण्डेय (सदस्य राज्यसभा), केन्द्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे, कैप्टन अभिमन्यु, केन्द्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी व विवेक ठाकुर (सदस्य राज्यसभा), क्षेत्रीय चुनाव प्रभारी (पश्चिम क्षेत्र) संजय भाटिया, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष व क्षेत्रीय चुनाव प्रभारी (कानपुर क्षेत्र) सुधीर गुप्ता, राष्ट्रीय मंत्री व क्षेत्रीय चुनाव प्रभारी (गोरखपुर) अरविन्द मेनन, क्षेत्रीय चुनाव प्रभारी (ब्रज) संजीव चौरसिया, राष्ट्रीय मंत्री व क्षेत्रीय चुनाव प्रभारी (अवध) सत्याकुमार, क्षेत्रीय चुनाव प्रभारी (काशी) सुनील ओझा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल, राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद डा. रमापतिराम त्रिपाठी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही उपस्थित रहे।

बसपा मुखिया मायावती का भाजपा पर हमला, बोलीं- भाजपा की डबल इंजन सरकार जुमलेबाजी, नहीं बढ़ी प्रति व्यक्ति आय

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। मायावती ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के डबल इंजन वाली सरकार के बयान पर तंज कसा है।

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने गुरुवार को सिलसिलेवार दो ट्वीट से भाजपा पर हमला बोला है। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश के निवासियों की प्रति व्यक्ति आय सही से नहीं बढने् अर्थात यहां के करोड़ों लोगों के गरीब व पिछड़े बने रहने सम्बंधी रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़े ही भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रहे हैं। मायावती ने कहा कि आंकड़े इस आमधारणा को प्रमाणित करते हैं कि भाजपा के विकास के दावे हवाहवाई व जुमलेबाजी हैं। उत्तर प्रदेश में तो इनकी डबल इंजन की सरकार में भी ऐसा क्यों है कि यहां पर प्रति व्यक्ति आय सही से नहीं बढ़ी।

बसपा मुखिया मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यहां पर भाजपा भाजपा के विकास के दावों के खोखले होने का पर्दाफाश होने से अब यह पार्टी तेजी से धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ व हिन्दू-मुस्लिम विवाद आदि के पुराने संकीर्ण मुद्दे पर वापस आ गई है। मायावती ने कहा कि लेकिन इनको शायद यह पता नहीं है कि लोग फिर से इनके छलावे में आने वाले नहीं हैं, जो उनके मूड से भी स्पष्ट है। भाजपा से लोगों का अब मोह भी भंग होता जा रहा है। बसपा मुखिया मायावती ने 20 सितंबर को महंत नरेन्द्र गिरि की संदिग्ध मौत के तीन दिन बाद दो ट्वीट से भाजपा पर हमला बोला है।

प्रदेश की जनता महसूस कर रही असुरक्षित, बोलीं अपना दल कमेरावादी अध्यक्ष कृष्णा पटेल

प्रयागराज। अपना दल (कमेरावादी) का दो दिवसीय अधिवेशन बुधवार को यहां सरदार पटेल संस्थान अलोपीबाग में संपन्न हुआ। समापन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने कहा कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ चढ़ता जा रहा है। हर व्यक्ति खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। देश असुरक्षित हाथों में है। कृष्णा पटेल का कहना था कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। युवा बेरोजगार होकर सड़क पर टहल रहे हैं। महिलाओं के हित के लिए कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। प्रदेश में सरकार बनने पर सभी के हित में योजनाएं चलाई जाएंगी।

प्रदेश में न तो रोजगार और न शिक्षा

अधिवेशन में अति विशिष्ट अतिथि डा. पल्लवी पटेल ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का बिगुल स्व. डा. सोनेलाल पटेल ने फूंका था। आज प्रदेश में रोजगार नहीं है। शिक्षा नहीं है। किसान तबाह हो गया है। महंगाई से लोगों की कमर टूटती जा रही है। डीजल-पेट्रोल, सरसो के तेल, गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। जनता की पहुंच से यह चीजें दूर होती जा रही हैं। प्रदेश में अपराध का ग्राफ सिर चढ़कर बोल रहा है। राज्य सरकार अपराधियों पर शिकंजा कसने में असफल साबित हुई है। अपना दल कमेरावादी ने हमेशा सभी वर्गों के हित के लिए कार्य किया है।

पंकज निरंजन पटेल, गंगाराम यादव, मानिकचंद्र पटेल, हरिश्चंद्र पटेल, मो. मोबिन अहमद, आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, उदल राजभर, विनोद, रमेश पटेल, राजकुमार पटेल, अजय पटेल आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

मिशन 2022 की तैयारी कर दी तेज

अपना दल कमेरावादी ने इस दो दिवसीय अधिवेशन के जरिए मिशन 2022 के लिए तैयारी तेज कर दी है। अपना दल कमेरावादी और अनुप्रिया पटेल के बीच सुलह की संभावनाएं फिलहाल बनती नहीं दिख रही हैं जबकि पिछले दिनों अनुप्रिया ने परिवार का विवाद खत्म करने के लिए अपनी ओर से पहल करते हुए बयान दिया था कि वह एमएलसी और मंत्री पद समेत अन्य समझौते करने के लिए तैयार हैं।

रुपयों के लिए घिनौनी हरकत कर रहा महिलाओं का गैंग, 68 वर्ष के बुजुर्ग पर छह माह में दुष्कर्म के पांच मुकदमे

गोरखपुर । सावधान...शहर में ऐसा गिरोह सक्रिय है, जो लोगों को दुष्कर्म के मामले में फंसाकर रुपये ऐंठ रहा है। गैंग की महिलाएं मास्टर माइंड के इशारे पर तहरीर देती हैं और रुपये मिलते ही चुप हो जाती हैं। एक बार जो चंगुल में फंसा उससे तब तक वसूली होती है, जब तक वह मना न कर दे। गैंग में पेशेवर महिला-पुरुषों के अलावा कानून के जानकार भी हैं, जो पर्दे के पीछे से गिरोह को संचालित करते हैं।

हालिया प्रकरण गीडा के 68 वर्षीय बुजुर्ग व्यापारी का है, जिन पर छह महीने में ही दुष्कर्म के पांच वाद दाखिल हो गए। अंजली, पानमती, शीला, सुशीला जैसे काल्पनिक नामों से दाखिल सभी वादों में आरोप एक ही था कि व्यापारी ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनके साथ दुष्कर्म किया। बेइज्जती और कानूनी झंझट से बचने के लिए व्यापारी ने जब तक रुपये दिए, तब तक मामला कचहरी से ही निपटता रहा और मना करने के बाद व्यापारी ही नहीं उनके दो बेटों पर भी दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करा दिया।

पुलिस ने विवेचना शुरू की तो शीला, सुशीला जैसे काल्पनिक नामों वाली महिलाएं दर्ज पते पर मिली ही नहीं। पुलिस ने दो मुकदमों में अंतिम रिपोर्ट (एफआर) लगाकर व्यापारी और उनके बेटों को क्लीनचिट दे दी। व्यापारी और उनके बेटों पर अब पांचवा मुकदमा भी दर्ज हो गया है, जिसकी विवेचना जारी है। यह गिरोह ऐसे लोगों को निशाना बनाता है, जो उन्हें चुपचाप रकम दे सकते हैं। व्यापारी अकेले नहीं हैं, इनके जैसे दर्जनों परिवार इस गिरोह के चंगुल में फंसकर तड़प रहे हैं।

पहले दो वाद अदालत से खारिज

अंजली और पानमती के नाम से नवंबर, 2020 में दो अलग-अलग वाद दाखिल हुए। दोनों में नौकरी दिलाने के नाम पर दुष्कर्म का आरोप था। गिरोह के संपर्क करने पर व्यापारी ने बेइज्जती के डर से समझौता कर लिया। रुपये मिलने के बाद चार पेशियों पर अंजली पहुंची न पानमती। नतीजा, दोनों वाद खारिज हो गए।

तीसरे-चौथे मुकदमे में एफआर

दो बार रुपये ऐंठ चुके गिरोह ने फिर रुपये मांगे। मना करने पर व्यापारी के खिलाफ शीला और सुशीला के नाम से तीसरा व चौथा वाद दाखिल हुआ। मुकदमा दर्ज करने का भी आदेश हो गया। पुलिस तक मामला पहुंचने पर घबराए व्यापारी परिवार को फिर समझौता करना पड़ा। विवेचना में वादी महिलाएं मिलीं न घर। पुलिस ने व्यापारी को क्लीन चिट देते हुए एफआर लगा दी। चार बार रुपये ऐंठने के बाद गिरोह ने व्यापारी व उनके दो पुत्रों पर दुष्कर्म व कुकर्म के आरोप में पांचवां वाद दाखिल किया। फोन कर पैसे मांगे। इसकी विवेचना चल रही है।

ऐसे ब्लैकमेल करता है गिरोह

गिरोह की महिला के नाम से न्यायालय में दुष्कर्म का वाद दाखिल किया जाता है। फिर संबंधित व्यक्ति को फोन पर दावा दाखिल होने की सूचना देकर समझौते की पेशकश की जाती है। व्यक्ति ने रुपये दे दिए तो ठीक वरना मुकदमा दर्ज कराने के लिए न्यायालय में पैरवी तेज हो जाती है। पुलिस से रिपोर्ट मांगे जाने के बाद गिरोह के सदस्य पुलिस बनकर पूछताछ का रुआब दिखाते हैं। थाने से पता करने पर व्यक्ति को मामला सही मिलता है। अधिकांश मामलों में इतने में समझौता हो जाता है। इतने पर भी रुपये नहीं देने वाले के खिलाफ गैंग की महिला बयान दर्ज करा देती है और मुकदमा दर्ज करने का आदेश हो जाता है।

बिहार में शराबबंदी कानून पर बड़ा फैसला, इन जगहों पर शराब रखने की अनुमति

पटना । बिहार सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को स्वीकृति दे दी। इसमें मद्य निषेध से जुड़े कई नियमों को स्पष्ट किया गया है। इसके तहत अगर किसी परिसर में शराब का निर्माण, भंडारण, बोतल बंदी, बिक्री या आयात-निर्यात होता है, तो वैसे पूरे परिसर को सीलबंद कर दिया जाएगा। मगर आवासीय परिसर में शराब मिलने पर सिर्फ चिह्नित भाग ही सीलबंद किया जाएगा न कि संपूर्ण परिसर। इसके अलावा छावनी क्षेत्र एवं मिलिट्री स्टेशन को शराब भंडारित करने की अनुमति होगी, मगर कैंटोनमेंट क्षेत्र से बाहर किसी भी कार्यरत या सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी को शराब रखने या उपभोग करने की अनुमति नहीं होगी।

24 घंटे कैमरे की निगरानी में होगा एथनाल उत्पादन

प्रविधान के तहत, अनाज एथनाल उत्पादित करने वाली अनाज आधारित डिस्टलरी की गतिविधि 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संचालित होगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि मादक द्रव्य से लदे वाहनों को राज्य सीमा में घोषित चेकपोस्ट से ही आने-जाने की अनुमति होगी। ऐसे वाहनों को हर हाल में 24 घंटे के अंदर राज्य की सीमा से बाहर निकल जाना होगा। निर्धारित रूट पर जैसे ही शराब लदी गाड़ी राजय की सीमा में प्रवेश करेगी इसमें डिजिटल लाक लग जाएगा।
90 दिनों के अंदर अधिहरण का देना होगा आदेश, कलेक्टर लेंगे निर्णय -अधिहरण का प्रस्ताव मिलने पर कलक्टर सुनवाई का यथोचित अवसर प्रदान करते हुए प्रभावी पक्षकार की उपस्थिति में 90 दिनों के अंदर अधिहरण का आदेश पारित करेंगे। प्रथम अपराध के लिए जमानत के लिए धारा 436 के प्रावधान लागू होंगे। कलक्टर के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की जा सकेगी जिस पर आयुक्त उत्पाद को 30 दिनों के अंदर आदेश पारित करना होगा।
पुनरीक्षण के लिए विभागीय सचिव को भी 30 दिनों के अंदर आदेश पारित करना होगा। बता दें कि अब तक शराब मिलने पर पूरे घर को सील कर दिया जाता रहा है। लेकिन इस कानून के प्रभावी होने के बाद व्यवस्था बदली रहेगी।

मुजफ्फरपुर के अहियापुर में बस की चपेट में आकर मोपेड सवार की मौत

मुजफ्फरपुर । अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहां में बुधवार दोपहर बस की चपेट में आकर मोपेड सवार की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोग जुट गए। इस पर चालक बस छोड़कर चालक भाग निकला। इससे घटनास्थल पर कुछ समय के लिए ट्रैफिक जाम की समस्या बन गई। अहियापुर थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के अनुसार उसकी पहचान सीतामढ़ी सहियारा जलानी के राम बहादुर ङ्क्षसह के रूप में हुई है।

बताते हैं कि मोपेड सवार राम बहादुर सीतामढ़ी से बेटी के घर अहियापुर के जमालाबाद आ रहे थे। इसी क्रम में झपहां के पास तेज रफ्तार बस ने मोपेड सवार को पीछे से रौंद दिया। घटना को देख स्थानीय लोग दौड़े। थाने को सूचना दी गई। आनन-फानन उन्हें एसकेएमसीएच पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुत्र आत्म प्रकाश के बयान पर उक्त बस व चालक के विरुद्ध पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। थानाध्यक्ष विजय कुमार ङ्क्षसह ने बताया कि बस को कब्जे में लिया गया है। चालक फरार है।
ट्रक की ठोकर से चाचा की मौत, भतीजा जख्मी- बरूराज थाना क्षेत्र के मुरारपुर चौक के समीप मोतीपुर-साहेबगंज पथ पर ट्रक की ठोकर से बाइक सवार एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जख्मी युवक को पीएचसी में भर्ती कराया। वहीं, मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मृतक की पहचान साहेबगंज थाना क्षेत्र के दोस्तपुर निवासी जगदीश महतो के 30 वर्षीय पुत्र जलेश्वर महतो के रूप में की गई है। जबकि जख्मी मृतक का भतीजा आकाश कुमार बताया गया है। पुलिस ने मौके से ट्रक एंव क्षतिग्रस्त बाइक को जब्त कर ली है। जानकारी के अनुसार बाइक सवार जलेश्वर महतो अपने भतीजा आकाश कुमार के साथ मोतीपुर बाजार से घर लौट रहे थे।

राज्यकर्मियों को एकमुश्त मिलेगा डीए, अक्टूबर में होगा भुगतान

पटना । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कुल 21 प्रस्तावों को सहमति दी गई। इसी क्रम में बिहार के सरकारी कर्मियों और पेंशनधारियों को सरकार ने एकमुश्त बकाया डीए (महंगाई भत्ता) भुगतान करने का निर्णय लिया है। अक्टूबर में जुलाई और अगस्त महीने के वेतन के साथ बकाया महंगाई भत्ते के भुगतान करने को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में छठा वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मियों को पहली जुलाई 2021 के प्रभाव से 164 की जगह 189 फीसद महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
पांचवां वेतनमान ले रहे कर्मियों को 356 फीसद महंगाई भत्ता - वहीं पांचवां वेतनमान की श्रेणी में आने वाले कर्मियों को

पहली जुलाई 2021 के प्रभाव से 312 की जगह 356 फीसद महंगाई भत्ता दिया जाएगा। राज्यकर्मियों को 2022 से 39 दिनों का अवकाश मिल सकेगा। इसपर भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी। कार्यपालक आदेश के तहत 15 छुट्टियां दी जाएंगी। इनमें तीन रविवार हैं। वहीं एनआइए एक्ट के तहत 21 छुट्टियां मिलेंगी। इसमें छह रविवार हैं। इसी तरह प्रतिबंधित व ऐच्छिक अवकाश 20 दिनों का होगा। इसमें से किसी तीन का उपयोग कर्मी कर सकेंगे।
कैबिनेट में हुए कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले - बता दें कि कैबिनेट की बैठक में हस्तकरघा और हस्तशिल्प निगम के साथ ही औषधि व रसायन विकास निगम के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति भी दी गई। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के संशोधन अध्यादेश 2021 के प्रारूप को भी स्वीकृति दी गई। इस दौरान बेगूसराय जिले के मंझौल के तत्कालीन सब जज सह एसीजेएम की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव को मंजूर किया गया। वहीं मुंगेर के खड़गपुर पीएचसी की चिकित्सा पदाधिकारी डा. अनामिका को पांच वर्षों तक लगातार गायब रहने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

राम को नहीं मानते जीतनराम, हिम्मत है तो अल्लाह पर बयान दें, पटना हाईकोर्ट के वकील ने दी चुनौती

पटना । भगवान श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल उठाकर पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी विवादों में आ गए हैं। भाजपा समेत अन्य दलों ने उनके इस बयान की निंदा की है। श्रीमद्भगवदगीता आपके द्वार अभियान के संस्थापक व पटना हाईकोर्ट के वकील संजीव मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को चुनौती दी है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा भगवान श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल उठाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। मिश्र ने कहा है कि मांझी में हिम्मत है तो वह ऐसा बयान अल्लाह के बारे में दें। बकौल मिश्रा, मांझी का बयान विवेक से परे है। पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा श्रीराम को जीवित और महापुरुष व्यक्ति नहीं मानने पर संपूर्ण विश्व आश्चर्यचकित है। श्रीराम पर ऐसी ओछी टिप्पणी करके अपनी बुद्धि भ्रष्ट होने जाने का स्वतः प्रमाण मांझी ने दे दिया है।

पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा भगवान श्रीराम को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा के कई मंत्रियों ने सवाल खड़ा किया है। पार्टी की ओर से भाजपा प्रदेश मुख्यालय में सहयोग कार्यक्रम के दौरान बुधवार को पत्रकारों के सवाल पर युवा एवं कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा ने कहा कि राम हम सबों के आराध्य एवं प्रेरणास्रोत हैं। बिहार के पाठ्यक्रम में राम के संदर्भ को शामिल किया जाए। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि भगवान राम हम सबों के आराध्य हैं, राम के अलावा कुछ नहीं। बता दें कि बुधवार को भी मांझी अपने बयान पर कायम रहे। उन्होंने कहा कि वे अब भी कहते हैं कि श्रीराम भगवान नहीं थे। वैसे यह उनका व्यक्तिगत विचार है।

प्रदेश की रैंकिंग से होगा निकायों के कार्यों का मूल्यांकन

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने स्वच्छता प्रेरणा कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा

- बेहतर काम नहीं करने वाले निकायों में होगा बदलाव
- रैंकिंग के आधार पर प्रमोशन भी मिलेगा

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने स्वच्छता की बुनियाद अभियान में नगरीय निकायों को सम्मानित किया।

भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने निकायों के कामकाज के तरीके पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि निकाय केवल स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए ही नहीं होते। हमें जनता की अपेक्षाओं पर खरा भी उतरना होगा। उन्होंने कहा कि अब हर तीन माह में प्रदेश की रैंकिंग से निकायों के कार्यों का मूल्यांकन होगा। विभाग अब रैंकिंग के आधार पर प्रमोशन भी देगा। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह बात गुरुवार को स्वच्छता प्रेरणा कार्यशाला एवं स्वच्छता की बुनियाद अभियान में नगरीय निकायों को सम्मानित करते हुए कही।

नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अब नगरीय निकायों के अधिकारियों के कामों पर विभाग की सीधी नजर होगी। बेहतर काम नहीं करने वाले निकायों में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को कई विषयों और प्रावधानों की जानकारी तक नहीं होती। यह स्थिति ठीक नहीं है। अफसरों को नसीहत देते हुए कहा कि निकायों के काम को काम की तरह नहीं मानवता के फर्ज की तरह निभाएं। जनता की अपेक्षा हमसे होती है, अपेक्षाओं पर हमें खरा भी उतरना होगा। निकाय केवल स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए नहीं होता।

नवाचार देखने दूसरे राज्यों में जाएंगे प्रदेश के अफसर

मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि देश के अन्य राज्यों में नगरीय विकास के क्षेत्र में हो रहे नवाचार और विकास के कार्यों को देखने अधिकारियों की टीम भेजी जाएगी। इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में योजनाओं के क्रियान्वयन पर विचार किया जाएगा। आंध्रप्रदेश में कचरा संग्रहण का कार्य अनुकरणीय है। श्री सिंह ने कहा कि स्वच्छता अभियान को निरंतरता देने के उद्देश्य से हर तीन माह में नगरीय निकायों का मूल्यांकन और उन्हें सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है।

दो अक्टूबर से होगा अमृत और स्वच्छ भारत मिशन फेज-2 का शुभारंभ

नगरीय विकास मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार आगामी दो अक्टूबर से अमृत और स्वच्छ भारत फेज-2 का शुभारंभ करेगी। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन शुरू हो चुका है। सिंह ने कहा कि सभी नगरीय निकाय इस संबंध में पहले से प्रोजेक्ट तैयार कर लें। उन्होंने बताया कि प्रदेश विभिन्न योजनाओं में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहा है। स्ट्रीट वेंडर फेज-1 में द्वितीय और फेज-2 में प्रथम स्थान पर है। फेज-2 में मप्र में सागर नंबर वन पर है। प्रमुख सचिव मनीष सिंह ने कहा कि स्वच्छता अभियान में इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के साथ ही नागरिकों को भी इससे जोड़ें। इस बात का विश्लेषण करें कि स्वच्छतम वार्डों में बीमारी की क्या स्थिति है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के मामले में प्रदेश के शहरों की चर्चा देश और विदेश में भी हो रही है। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 के लिए जनवरी में सर्वे होगा। इसके लिये अभी से पूरी तरह से तैयारी करें और पिछली बार से बेहतर रैंक लाएं। प्रदेश के 36 नगरीय निकायों को कुल 71 सम्मान के लिये चयनित किया गया है। राज्य स्तर के 29 और संभाग स्तर के 42 सम्मान दिये गये हैं। मिशन संचालक गौरव बैजल ने स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों की जानकारी दी। इस दौरान निकायों को बेहतर काम पर राज्य स्तरीय और संभाग स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए गए।

सीएम आज सागर संभाग को देंगे 119 करोड़ से अधिक के कार्यों की सौगात

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जन-कल्याण और स्वराज अभियान में 24 सितंबर को पन्ना जिले में आयोजित कार्यक्रम में सागर संभाग को स्वास्थ्य के क्षेत्र में 119 करोड़ 83 लाख 66 हजार के 38 कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री जिला चिकित्सालय निवाड़ी को 10 करोड़ रुपए की लागत से 60 से 100 बिस्तरों में और जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ को 20 करोड़ रुपए की लागत से 200 से 300 बिस्तरीय भवन उन्नयन और निर्माण कार्य का भूमि-पूजन करेंगे।

पन्ना में होगा जन-कल्याण व स्वराज अभियान के तहत कार्यक्रम

सीएम 40 करोड़ की लागत से छतरपुर जिले के बड़ामलहरा, पन्ना जिले के पवई, सागर जिले के बंडा, राहतगढ़ के 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बिस्तरीय सिविल अस्पतालों के भवन उन्नयन एवं निर्माण कार्यों की सौगात देंगे, 22 करोड़ 95 लाख लागत के छतरपुर जिले के महाराजपुर, मातगुवां, टीकमगढ़ जिले के बम्हौरीकला और लिधौरा के 06 बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन और उन्नयन कार्यों का शिलान्यास करेंगे। चौहान 18 करोड़ 47 लाख की लागत के सागर जिले के सिलौंधा, खैराना, झिला, चितौरा, पन्ना जिले के सारंगपुर, दमोह जिले के लुहारी, छतरपुर जिले के बम्होरी, ठकुर्रा, टीकमगढ़ जिले के ककरवाड़ा और निवाड़ी जिले के मडिया के 06 बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नयन और निर्माण कार्य की सौगात देंगे।

ऑक्सीजन प्लांट का भी करेंगे लोकार्पण: मुख्यमंत्री पांच करोड़ 93 लाख 22 हजार के सागर जिले में पडरिया, तिन्सुआ, पुत्तर्रा, पाटन, पन्ना जिले के बहादुरगंज, नचने, दमोह जिले के चिलोद, बोरदा, छतरपुर जिले के जुझारपुरा, बराखेरा, लुहरपुरा, टीकमगढ़ जिले के तालमउ, उपरारा और निवाड़ी जिले के जनौली उप स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री जिला चिकित्सालय छतरपुर, सिविल अस्पताल हटा और पन्ना जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ में और जिला अस्पताल सागर में दो करोड़ 48 लाख लागत के ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे।

आयुष्मान योजना में शामिल होंगे 4.7 करोड़ लोग : डॉ. चौधरी

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने दी पत्रकार वार्ता में जानकारी

भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश में आयुष्मान भारत निरामयम् योजना में प्रदेश के 4.7 करोड़ लोगों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए प्रदेश में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आयुष्मान 2.0 अभियान चलाया जा रहा है।

यह जानकारी गुरुवार को आयुष्मान भारत निरामयम् को मप्र में लागू हुए तीन वर्ष पूरा होने के मौके पर पत्रकार वार्ता के दौरान लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि योजना प्रदेश में 23 सितंबर 2018 को लागू की गई थी, तब से लेकर अब तक आयुष्मान योजना के कार्ड बनाने का काम जारी है। अब तक प्रदेश में 2.54 करोड़ लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बेहद वरदान साबित हुआ है। बीमारी के मुश्किल समय में यह कार्ड बड़ा सहारा बना हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में योजना के तहत 9.54 लाख उपचार प्रक्रियाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को दिया गया है। इस पर अब तक 1373 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है। योजना में पांच लाख रुपए तक की निःशुल्क उपचार की सुविधा दी जा रही है। योजना के तहत प्रदेश में 895 अस्पतालों को चिन्हित किया गया है, इनमें 440 निजी और 455 सरकारी अस्पताल शामिल हैं। योजना में अधिक से अधिक अस्पतालों को जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अस्पतालों में भर्ती होने की स्थिति में कोरोना, कैंसर, गुर्दा रोग,हृदय रोग डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, डायलिसिस, घुटना व कूल्हा प्रत्यारोपण, निःसंतानता, मोतियाबिंद सहित अन्य गंभीर बीमारियों का निःशुल्क उपचार करने की सुविधा इस योजना के तहत दी गई है।

अब तक एक लाख 35 हजार अपात्रों के कार्ड निरस्त

पत्रकार वार्ता के दौरान डॉ. चौधरी ने बताया कि प्रदेश में अपात्र व्यक्ति द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने की शिकायत होने के बाद मामले की जांच कराई गई है, इसमें अब तक एक लाख 35 हजार अपात्रों के कार्ड निरस्त किए गए हैं। हालांकि ऐसे अपात्रों द्वारा कार्ड बनाने पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने संबंधी सवाल का वे जवाब नही दे सके। अनुबंधित अस्पतालों द्वारा मनमाना बिल बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि अस्पताल ज्यादा बिल बनाते हैं, तो मामले की शिकायत टोल फ्री नंबर पर की जा सकती है। कोविड काल में अस्पतालों द्वारा मनमाने वसूली पर उन्होंने कहा कि कोविड काल में 350 अस्पतालों को संबद्ध किया गया था। सभी जिलों से एक या दो अस्पतालों के बारे में इस तरह की शिकायत मिली।

पदोन्नति में आरक्षण के लिए हुई दूसरी बैठक में मंत्री समूह ने विधिवत सुने पक्ष

रोस्टर से मिले आरक्षण : अजाक्स सपाक्स ने कहा, यह उचित नहीं

भोपाल (एजेंसी)। पिछले पांच साल से विभागों में बंद पड़े प्रमोशन चैनल को शुरू करने के लिए सरकार में लगातार सक्रियता बढ़ रही है। सरकार द्वारा गठित मंत्री समूह ने गुरुवार को दूसरी बैठक में आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग से संबंधित लोक सेवकों के संगठनों की ओर से विधिवत पक्ष सुने। अजाक्स ने जहां इस प्रक्रिया में रोस्टर का पालन करने की बात कही, तो सपाक्स ने कहा कि यह कहीं से भी उचित नहीं है।

गुरुवार को बल्लभ भवन में बुलाई गई मंत्री समूह की दूसरी बैठक में गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार उपस्थित थे। यह बैठक गृहमंत्री के कक्ष में ही आयोजित हुई थी। सबसे पहले अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संगठन यानी अजाक्स का पक्ष लिया गया।

इस बैठक में अजाक्स संगठन की ओर से प्रांत अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय सेवा के वरिष्ठ अधिकारी जेएन कंसोटिया, महासचिव एसएल सूर्यवंशी एवं गौतम पाटिल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इन्होंने पक्ष रखा कि पदोन्नति के नए नियम में रोस्टर तैयार होना चाहिए। इसमें संख्या अनुपात का पैमाना भी तय होना जरूरी है। इसके आधार पर संविधान के मुताबिक अनुसूचित जाति को 20 जबकि अनुसूचित जनजाति को 16 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। इसी प्रक्रिया के तहत प्रतिनिधित्व आवश्यक है। यहां सरकार की ओर से मौजूद सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने भी कहा कि उनकी मांग के अनुसार पर्याप्त आरक्षण मिलेगा, लेकिन अजाक्स पदाधिकारी इस बात पर अडिग रहे कि पर्याप्त की परिभाषा को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

इधर सपाक्स संगठन की ओर से अध्यक्ष केएस तोमर, सचिव एके जैन ने कहा कि पहले से ही इस वर्ग को पदोन्नतियों में पर्याप्त आरक्षण मिल रहा है। नतीजतन रोस्टर की कोई जरूरत नहीं है। इस वर्ग का पदोन्नतियों में पहले से ही पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। इस कारण रोस्टर लागू नहीं किया जाना चाहिए। एके जैन के अनुसार उन्होंने दूसरी बैठक में भी यही बात कही है कि पहले कोर्ट का निर्णय आ जाए। उसके बाद ही नए नियम लागू होना चाहिए।

गुरुवार को भोपाल स्थित मंत्रालय में प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में पदोन्नति मे पात्रता अनुसार लाभ देने के लिए मंत्री समूह की बैठक हुई। जिसमें अजाक्स एवं सपाक्स के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

संक्षिप्त समाचार

भाजपा प्रत्याशी डॉ. मुरुगन का नामांकन-पत्र वैध

भोपाल । मध्यप्रदेश से राज्यसभा की रिक्त एक सीट की पूर्ति हेतु उप निर्वाचन के लिए भाजपा के उम्मीदवार डॉ. मुरुगन का नामांकन वैध पाया गया। उप निर्वाचन हेतु नामांकन केअंतिम दिन तक कुल एक नामांकन-पत्र ही दाखिल किया गया था। गुरुवार दोपहर 2.00 बजे से प्राप्त नामांकन-पत्रों की संवीक्षा राज्यसभा उप निर्वाचन-2021 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर अवधेश प्रताप सिंह के द्वारा की गई। संवीक्षा के दौरान राज्यसभा उप निर्वाचन के सहायक रिटर्निंग आफिसर बीडी सिंह,अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार कौल,उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रमोद शुक्ला मौजूद थे। राज्यसभा के उप निर्वाचन,2021 की अधिसूचना अनुसार अभ्यर्थिता से नाम वापसी दिनांक 27 सितंबर-2021 को अपराह्न 3.00 बजे तक हो सकेगी।

मक्का को लेकर दिग्विजय ने लिखा शिवराज को पत्र

भोपाल । मक्के की उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र लिखा है। दिग्विजय सिंह ने सीएम को सरकार द्वारा किसानों को मक्के की उपज समर्थन मूल्य में नहीं खरीदे जाने से हो रही समस्याओं से अवगत कराया। दरअसल प्रदेश सरकार खरीफ फसल समर्थन मूल्य 2021 में ज्वार, बाजरा व धान को ही शामिल किया है जबकि समूचे मध्यप्रदेश में इन फसलों का उत्पादन कम मात्रा में किया जाता है और मक्के की फसल का उत्पादन पूरे मध्यप्रदेश में अधिक मात्रा में होता है लेकिन मक्के की फसल का समर्थन मूल्य में खरीदी का सरकार रजिस्ट्रेशन ही नही कर रही है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री से मक्के को समर्थन मूल्य में खरीदने का अनुरोध करते हुए लिखा है कि किसान पिछले दो साल से मक्के की फसल में नुकसान सहन कर रहे हैं यदि इस वर्ष भी मध्यप्रदेश सरकार मक्के की समर्थन मूल्य में खरीदी नहीं करेगी तो किसान पूरी तरह घाटे में चले जाएगे।

पीड़िता के इलाज का इंतजाम करे सरकार: अर्चना

भोपाल । बुधवार को पन्ना में 12वीं की छात्रा के साथ हुई हृदयविदारक घटना पर मप्र महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. अर्चना जायसवाल ने दु:ख व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में अपराधी लगातार बेखौफ हो अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। श्रीमती जायसवाल ने कहा कि जो सहायता पीड़िता को सरकार द्वारा प्रदान की गई है वह कहीं से भी सही नहीं है, सरकार ना सिर्फ पीड़िता का पूरा इलाज का खर्चा उठाए, अपितु उसकी भविष्य में सुरक्षा का पूरा पुख्ता इंतेजाम भी करे, साथ ही तीन लाख का मुआवजा भी प्रदान करे। श्रीमती जायसवाल ने बताया कि महिला कांग्रेस की पदाधिकारी पीड़िता से गुरुवार सुबह ही भेंट कर हाल ले चुकी हैं और वे स्वयं भी इस घटनाक्रम पर पूरी नजर रखे हैं।

भाजपा सरकार में किसान पूरी तरह बर्बाद हो गए : पटवारी

भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश में कृषि से जुड़े कार्यों में प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लेकर प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला है।

गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पटवारी ने कहा कि शिवराज सरकार मध्यप्रदेश की अब तक की सबसे ज्यादा किसान विरोधी सरकार है। मुख्यमंत्री आज किसानों को बीज बांटने का नाटक कर रहे हैं। जबकि किसानों को जब बीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब सोयाबीन का बीज बाजार से गायब था। निमाड़ के इलाके में सूखा पड़ा हुआ है और शिवराज सरकार ने आज तक वहां के किसानों की सुध नहीं ली। इंदौर और आसपास के इलाके में आलू का किसान बुरी तरह परेशान है। मूंग के किसान की दुर्दशा सब को पहले से ही पता है।

शिवराज सरकार द्वारा ग्राम बीज बनाने के दावे को हास्यास्पद बताते हुए पटवारी ने कहा कि पहले बीज उत्पादक सहकारी समितियों के घोटाले का हिसाब दें जिन्होंने सरकारी अनुदान से बीज बनाकर निजी कंपनियों को बेच बेच दिए। सरकार यह बात स्पष्ट करे कि बीज विकास निगम किसानों को बीज उपलब्ध कराने में सक्षम है या नहीं। अगर सक्षम है तो किसानों को सोयाबीन का बीज क्यों नहीं मिल सका।

प्रदेश सरकार नवंबर और निर्वाचन आयोग अक्टूबर में पंचायत चुनाव करवाने के मूड में

भोपाल । प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाती रही हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने भी निकाय चुनाव करवाने को लेकर बीते दिनों संकेत दिए थे, लेकिन चुनाव टाल दिए गए। अब पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सरकार जहां नवंबर में पंचायत चुनाव करवाने के पक्ष में है, वहीं निर्वाचन आयोग अक्टूबर माह में चुनाव करवाने की तैयारियां कर रहा है। जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग अब निकाय चुनावों से पहले पंचायत चुनाव करवाने को तैयार है। पंचायत चुनाव प्रक्रिया को लेकर आयोग ने सभी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली है। इस बीच राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव नवंबर माह में करवाने की मांग की है। सरकार अक्टूबर में त्यौहारी सीजन होने से इस माह में चुनाव के पक्ष में नहीं है,जबकि निर्वाचन आयोग अक्टूबर में पंचायत चुनाव करवाने के बाद दिसंबर में निकाय चुनाव करवाने की योजना बना रहा है। आयोग ने हाईकोर्ट में एक आवेदन दिया है जिसमें सरकार को जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण करने और पंचायत चुनाव को अक्टूबर में करवाने की मांग की है। निर्वाचन आयोग के अनुसार अगर इस साल दिसंबर तक निकाय चुनाव नहीं हुए तो फिर अगले साल 2022 मार्च तक चुनाव नहीं होंगे। साल बादलने के बाद आयोग को नए सिरे से मतदाता सूची तैयार करना होगी, जिसमें समय लगेगा। यही वजह है कि आयोग अक्टूबर में पंचायत और दिसबंर में निकाय चुनाव करवाने की तैयारी में है।

अजय सिंह को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे मिश्रा और विजयवर्गीय

भोपाल । वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय गुरुवार को उनके निवास पर पहुंचे। गृहमंत्री द्वारा अजय सिंह को जन्मदिन की बधाई देने और दो दिन पूर्व ही अजय सिंह द्वारा गृहमंत्री से उनके निवास पर मुलाकात करने का लेकर राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। गृहमंत्री डॉ. मिश्रा के बाद श्री विजयवर्गीय भी अजय सिंह को बधाई देने पहुंचे। राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने बताया कि यह एक शिष्टाचार परंपरा के तहत मुलाकात हुई है। अजय सिंह पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और डॉ. मिश्रा एवं विजयवर्गीय के साथ उनके पुराने संबंध हैं, इसी नाते दोनों नेताओं ने पार्टी की परंपरा के तहत उनके निवास पर पहुंचकर जन्मदिन की बधाई दी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी अजय सिंह को पुष्प गुच्छ भेंट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

भाजपा के सेवा और समर्पण अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य परीक्षण शिविर को संबोधित करते हुए वीडी शर्मा कहा

हर वर्ग और समाज के लिए खड़ा है भाजपा कार्यकर्ता

71 लाख टीकों का लक्ष्य पार करने पर प्रदेश अध्यक्ष ने दी बधाई

भोपाल (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर भाजपा द्वारा शुरू किए गए सेवा और समर्पण अभियान के तहत प्रदेश सरकार के 71 लाख कोरोना टीके लगवाने का लक्ष्य हासिल करने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है।

सेवा और समर्पण अभियान के अंतर्गत भोपाल में आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार के साथ चलाए जा रहे इस अभियान में आज तक 73 लाख 50 हजार से ऊपर वैक्सीनेशन हो चुका है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री चौहान, स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, अधिकारी, कर्मचारियों और भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों से लेकर बूथ के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि हमारा कार्यकर्ता हर समाज, वर्ग की सहायता के लिए खड़ा है।

श्री शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सेवा और समर्पण अभियान के तहत 57 संगठनात्मक जिलों में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाए हैं। जिसमें बड़ी संख्या में आमजन भाग ले रहे हैं। पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉ. अभिजीत देशमुख सभी जिलों में डॉक्टरों के साथ इस अभियान की सफलता के लिए काम कर रहे हैं और इस आयोजन के लिए मैं पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ को शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी लगातार इस काम में लगे हुए हैं।

सेवा कार्यों से सामाजिक भूमिका का निर्वाह कर रही पार्टी

श्री शर्मा ने कहा कि अब पार्टी ने तय किया है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से मुकाबले के लिए हमें प्रत्येक बूथ पर चार स्वास्थ्य स्वयंसेवक बनाना है। हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ ने डॉक्टरों की चैन बनाई है, जिसमें चार हजार से अधिक डॉक्टर जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि यदि तीसरी लहर आती है तो यह स्वास्थ्य स्वयंसेवक और कार्यकर्ता जनता की सेवा में खड़े होंगे। इस अवसर पर प्रदेश सह संगठन महामंत्री हितानंद जी, अजा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, प्रदेश महामंत्री भगवानदास सबनानी, प्रदेश शासन के मंत्री विश्वास सारंग, प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर, चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अभिजीत देशमुख, कार्यक्रम प्रभारी शंकर मकोरिया, आरके बघेल, नित्यानंद शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे।

कुपोषण मुक्त होगा मेरा लाकसभा क्षेत्र-प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो गरीब बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, उनको कुपोषण से मुक्त कराना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैंने यह संकल्प लिया है मेरे लोकसभा क्षेत्र में कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं रहेगा। इसके लिए समाज और सरकार मिलकर आगे आए हैं।

राज कुन्द्रा को पोर्नोग्राफी केस में राहत

फिल्म एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिज़नेसमैन राज कुन्द्रा को पोर्नोग्राफी केस में आखिरकार जमानत मिल गई है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी है। राज कर अश्लील फिल्म बनाने और उसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का आरोप है और 19 जुलाई को पुलिस ने उन्हें अपने कब्जे में कर लिया था। राज के वकील प्रशांत पाटिल के अनुसार सेलिब्रिटी और प्रोड्यूसर ये फैसला लेते थे कि क्या अपलोड होना है। राज कभी यह तय नहीं करते थे। 1400 पृष्ठों की चार्जशीट में एक भी सबूत ऐसा नहीं है जो दर्शाता हो कि राज ये अपलोड करते थे। गौरतलब है कि राज की गिरफ्तारी के बाद बॉलीवुड में हड़कंप मच गया था। शिल्पा और उसके फैंस दंग रह गए थे। शिल्पा भी शुरुआत में परेशान हुईं, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आपको संभाला। इस मामले की जांच पुलिस फरवरी 2021 से कर रही थी। राज के खिलाफ जब शिकायत हुई तो पुलिस ने बारीकी से जांच की और फिर राज को पकड़ा।

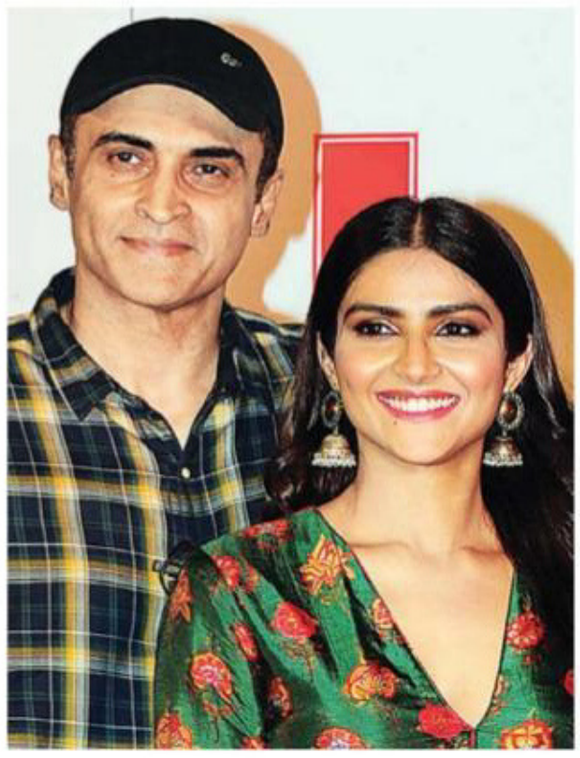

प्रनूतन ने की अपने डिजिटल डेब्यू हेलमेट पर

पिता मोनीश बहल की प्रतिक्रिया शेयर

जी5 की लोकप्रिय फिल्म हेलमेट शानदार ढंग से आगे बढ़ रही है और इस विषय पर कई लोगों का दिल जीत रही है। इस महीने की शुरुआत में रिलीज हुई फिल्म में अपारशक्ति खुराना और प्रनूतन जैसे सितारे कंडोम खरीदने के विषय को सामान्य करने की बात करते नज़र आ रहे हैं। अभिनेत्री प्रनूतन बहल की फ़िल्म को हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया था। अपनी फिल्म के बारे में बात करते हुए अभिनेत्री ने बताया कि उन्हें सबसे अच्छी प्रतिक्रिया उनके पिता मनीष बहल से मिली थी। उसी के बारे में बात करते हुए, प्रनूतन ने उल्लेख किया, 'पिताजी को फिल्म पसंद आई। फिल्म देखने के बाद उन्होंने पहली बात यह कही कि उन्हें मेरी पसंद पर गर्व है और उन्हें यह फिल्म बहुत अच्छी लगी। उन्होंने महसूस किया कि हेलमेट एक संपूर्ण पैकेज है जिसमें मस्ती, कॉमेडी और एक महत्वपूर्ण संदेश है। उन्हें गर्व और इम्प्रेस्ड महसूस होता देखकर मुझे अलग-अलग विषयों को चुनने की प्रेरणा मिलती है, जो मुझे लगता है कि डिफरेंस पैदा कर सकती है। फिल्म हेलमेट स्ट्रीमिंग के लिए ज़ी5 पर उपलब्ध है।

पहली बार साइंस फिक्शन जॉनर में काम करेंगे अली फजल

अभिनेता अली फजल ने एक आगामी बिना शीर्षक वाली साइंस फिक्शन लघु फिल्म की शूटिंग की है, जिसे हाल ही में चार दिनों के लिए मुंबई में फिल्माया गया था। फिल्म का लेखन और निर्देशन कार्गो की निर्देशक आरती कदव ने किया है। उनकी पिछली लघु फिल्म 55 किमी/सेकंड थी, जिसमें ऋचा चड्ढा मुख्य भूमिका में थीं। अली ने कहा कि आरती के साथ सहयोग करना एक अद्भुत अनुभव रहा है। मुझे वास्तव में उसके साथ शूटिंग करने में बहुत मजा आया और मुझे लगता है कि वह जो करती है उसमें वह बेहद प्रतिभाशाली है। उन्होंने आगे कहा कि हमने मुंबई में सिर्फ चार दिनों के अंतराल में पूरी फिल्म की शूटिंग की। काश मैं लघु फिल्म के बारे में और अधिक साझा कर पाता, लेकिन पहले आधिकारिक घोषणा की प्रतीक्षा करें। फिल्म के बारे में विवरण अभी भी गुप्त रखा गया है।

नेहा कक्कड़ ने फैमिली प्लानिंग को लेकर किया खुलासा

नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह की शादी के बाद से उनकी फैमिली प्लानिंग को लेकर चर्चा हो रही है। कई बार ऐसी अफवाहें भी उड़ीं कि नेहा कक्कड़ प्रेग्नेंट हैं। अब हाल ही में वह डांस रियलिटी शो 'डांस दीवाने 3' के मंच पर पहुंचीं जहां उनके साथ भाई टोनी कक्कड़ और सिंगर हनी सिंह थे। इस दौरान नेहा ने बच्चे को लेकर बात की।

-फैमिली प्लानिंग को लेकर कही ये बात

शो में एक कंटेस्टेंट गुंजन ने 'लुंगी डांस' गाने पर जबरदस्त परफॉर्म किया। गुंजन को डांस करते हुए देख नेहा ने कहा कि 'रोहू और मैंने अभी सोचा नहीं है बेबी का लेकिन अगर कभी बेबी करे तो हम चाहेंगे कि गुंजन जैसी हो।' नेहा की ये बातें सुनकर गुंजन मुस्कुराने लगती हैं।

-पहली मुलाकात से शादी तक

नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह ने पिछले साल अक्टूबर में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी की थी। उन्होंने सेलिब्रेशन दिल्ली में किया था। सोशल मीडिया पर नेहा और रोहनप्रीत की शादी के कई फोटोज और वीडियोज वायरल हुए थे। दोनों 'नेहू द व्याह' गाने के दौरान रिलेशनशिप में आए थे। पहली मुलाकात गाने की शूटिंग के दौरान ही हुई थी।

-प्रेग्नेंसी की उड़ी थी अफवाह

शादी के दो महीने बाद ही उनकी प्रेग्नेंसी की अफवाहें तब उठी थीं जब उन्होंने एक तस्वीर साझा की जिसमें उनका बेबी बंप दिखाई दिया। हालांकि जल्दी ही उन्होंने दूसरा पोस्ट करके यह बता दिया कि यह उनके आने वाले म्यूजिक वीडियो के लिए है।

ब्रिटनी ने 6 दिनों के डीएक्टिवेशन के बाद इंस्टाग्राम पर की वापसी

ब्रिटनी स्पीयर्स ने अपने इंस्टाग्राम को फिर से सक्रिय किया है। इंस्टाग्राम से उनका छोटा ब्रेक आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है। बिलबोर्ड डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में सगाई करने वाली गायिका ने सोमवार को अपना खाता फिर से सक्रिय कर दिया। उन्होंने अपने प्रशंसकों से कहा कि वह अपनी सगाई की खबर का जश्न मनाने के लिए अपने होने वाले पति सैम असगरी के साथ एक संक्षिप्त यात्रा पर जाने के बाद बस अपने उत्साह को नियंत्रित नहीं कर सकती है। स्पीयर्स ने अपने फीड पर तस्वीरों की एक श्रृंखला पोस्ट की और लिखा, मेरे सप्ताहांत की छुट्टी के कुछ शॉट्स, मैंने मेरे मंगेतर के साथ मेरी सगाई का जश्न मनाया, मुझे अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं इंस्टा से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती थी इसलिए मैं पहले ही वापस आ गई हूँ। स्पीयर्स और असगरी ने 12 सितंबर को इंस्टाग्राम के जरिए अपनी सगाई की घोषणा की थी। स्पीयर्स ने अपनी सगाई की अंगूठी भी दिखाई थी। असगरी के मैनेजर ब्रैंडन कोहेन ने बाद में बिलबोर्ड को दिए एक बयान में कहा कि युगल ने आज अपने लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते को आधिकारिक बना दिया है और उनके प्रति व्यक्त किए गए समर्थन, समर्पण और प्यार से बहुत प्रभावित हैं।

शाहरुख खान ने मुझे कई फिल्मों से निकलवाया-ऐश्वर्या

एक समय पर शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता था। मगर इनके बीच कुछ ऐसा विवाद हुआ कि शाहरुख खान ने अपनी कई फिल्मों से ऐश्वर्या राय को निकलवा दिया था।

बॉलिवुड के बादशाह शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय ने साथ में कम ही फिल्में की हैं मगर इनकी जोड़ी को हमेशा पसंद किया गया है। शाहरुख और ऐश्वर्या ने साथ में देवदास, मोहब्बतें और जोश जैसी फिल्में दी हैं। हालांकि एक समय ऐसा भी आया था जबकि शाहरुख और ऐश्वर्या के संबंध काफी खराब हो गए थे। इसके बाद शाहरुख ने ऐश्वर्या को कई फिल्मों से निकलवा दिया था। जानें क्या था पूरा मामला।

सलमान बने थे शाहरुख और ऐश्वर्या के बीच विवाद का कारण?

शाहरुख खान की फिल्म चलते चलते में पहले लीड रोल में ऐश्वर्या राय को लिया जाना था। इसी समय पर ऐश्वर्या और सलमान का रिलेशनशिप बेहद बुरे दौर से गुजर रहा था। कहा जाता है कि सलमान खान अक्सर ऐश्वर्या की फिल्म के सेट पर आकर मुश्किलें खड़ी करते थे। कहा जाता है कि सलमान ने एक बार ऐश्वर्या के साथ मारपीट भी की। इसके बाद शाहरुख ने फैसला लिया कि चलते चलते में ऐश्वर्या की जगह रानी मुखर्जी को कास्ट किया जाए।

-एक, दो नहीं बल्कि 5 फिल्मों से ऐश्वर्या को निकाला

कहा जाता है कि चलते चलते के बाद ऐश्वर्या को ऐसी 5 फिल्मों से निकाल दिया गया जिनमें उनके ऑपोजिट शाहरुख खान थे। इनमें से एक फिल्म वीर जारा थी जिसमें ऐश्वर्या वाला रोल प्रीति जिंटा को दिया गया। शाहरुख के ऑपोजिट बाकी की फिल्में कौन सी थीं इनकी ज्यादा जानकारी नहीं मिली है।

-ऐश्वर्या ने भी मानी थी फिल्मों से निकाले जाने की बात

ऐश्वर्या राय ने भी बाद में सिमी ग्रेवाल के टॉक शो में इस बात को माना था कि उन्हें शाहरुख की फिल्मों से निकाला गया था। ऐश्वर्या ने कहा था, हां, एक समय पर कुछ फिल्मों में हमारे (शाहरुख के साथ) काम करने की बातें चल रही थीं लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मुझे उन फिल्मों से निकाल दिया गया। मुझे पता भी नहीं कि ऐसा क्यों हुआ था। अगर कोई इसके बारे में बोलना चाहता है तो ठीक है मगर अगर इसका कोई कारण नहीं बताया जाता तो मतलब है कि वह बात ही नहीं करना चाहते। मैं किसी के पास इस बारे में पूछने भी नहीं गई।

-बाद में शाहरुख ने मांगी थी माफी

कहा जाता है कि बाद में साल 2009 में शाहरुख खान ने करण जौहर की बर्थडे पार्टी में ऐश्वर्या से माफी मांगी थी कि उनके मुश्किल समय वह मदद नहीं कर सके। ऐश्वर्या ने शाहरुख को माफ भी कर दिया था। इसके बाद शाहरुख और गौरी अपने साथ ऐश्वर्या और अभिषेक को अपने घर मन्नत ले गए थे और चारों ने सुबह तक पार्टी की थी।

मेरे फिटनेस सफर ने लोगों का नजरिया बदल दिया-अर्जुन

मोटापे से जूझ रहे अभिनेता अर्जुन कपूर का कहना है कि उनकी फिटनेस यात्रा ने लोगों के उन्हें देखने का नजरिया बदल दिया है और उनके पास आने वाले फिल्म ऑफर भी बदल गए हैं। अर्जुन ने कहा, लोगों ने मेरे परिवर्तन को नोटिस किया है। मेरी फिटनेस यात्रा ने न केवल मेरे भोजन, पोषण और फिटनेस को देखने के तरीके को बदल दिया है, बल्कि लोगों के मुझे देखने के तरीके को भी बदल दिया है। मेरे पास आने वाले अवसर और प्रस्ताव भी बदल गए हैं। भोजन और फिटनेस के क्षेत्र में कदम रखते ही अर्जुन के पास कुछ रोमांचक नई घोषणाएं होंगी। अभिनेता ने कहा, मैंने निश्चित रूप से भोजन और पोषण के क्षेत्र में खुद को तलाशने के लिए कई बातचीत शुरू की है और मैं कुछ चीजों के लिए उत्साहित हूं जो जल्द ही पूरी हो जाएंगी। मैं आने वाले दिनों में और अधिक ठोस विवरण साझा करने की स्थिति में रहूंगा।अर्जुन, जो वर्तमान में अपनी अगली एक विलेन 2 की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, उनका कहना है कि वह उन उपक्रमों का हिस्सा बनना चाहते हैं जो फिटनेस स्पेस में क्रांति लाने का लक्ष्य रखते हैं।

भूमि ने समग्र सौंदर्य की वकालत की

बॉलीवुड अदाकारा भूमि पेडनेकर के लिए आईने के सामने बिताया गया समय चिकित्सीय से कम नहीं है। समग्र सुंदरता की हिमायती भूमि का कहना है कि वह सौंदर्य के प्रति बहुत उत्साही हैं और खुद की अच्छे से देखभाल करती हैं। भूमि अपने पहले ब्रांड एंबेसडर और सौंदर्य सहयोगी के रूप में एक बहु-सौंदर्य तकनीक मंच, बोडेस डॉट कॉम के साथ जुड़ गई है। खुदरा विक्रेता लोगों के सौंदर्य की खोज के तरीके को बदलने की इच्छा रखती है। यह मंच महिला के सशक्त नारीत्व की भावना से प्रेरित है और इसका उद्देश्य भारत में सौंदर्य उद्योग में अपनी त्वचा देखभाल, कल्याण, मेकअप और सौंदर्य उत्पादों के साथ एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल करना है।

मशहूर एक्ट्रेस पर एसिड अटैक की कोशिश

पायल घोष, यह नाम तब चर्चा में आया था जब इस बंगाली एक्ट्रेस ने बॉलीवुड के मशहूर निर्माता-निर्देशक अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा कर सनसनी फैला दी थी। अब एक बार फिर पायल सुर्खियों में हैं। पायल ने एक वीडियो जारी कर सनसनीखेज खुलासा किया है। पायल ने वीडियो में कहा है कि उन पर एसिड अटैक की कोशिश की गई। वे अंधेरी स्थित अपने घर से निकल कर जैसे ही कार में बैठी उन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और एसिड फेंकने की कोशिश की। हमलावरों ने पायल पर रॉड से भी हमला किया जिससे उन्हें मामूली चोट भी आई। वे पायल का सामान भी छीन कर भाग गए। उन्होंने चेहरे पर मास्क लगा रखा था इसलिए पायल उन्हें पहचान नहीं सकी। पायल के अनुसार उन्होंने हमलावर के हाथ में एसिड जैसा कुछ देखा तो वे फौरन चिल्लाईं जिसके कारण हमलावर भाग खड़े हुए, लेकिन खुद को बचाने में उन्हें चोट आ गई। पायल ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है।

आईपीएल 2021: दिल्ली कैपिटल्स ने फिर किया शीर्ष पर कब्जा, चेन्नई को छोड़ा पीछे

दुबई (एजेंसी)।

आईपीएल 2021 के 33वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया. इस जीत के बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम अंकतालिका में पहले पायदान पर पहुंच गई और उसने चेन्नई सुपर किंग्स को पीछे छोड़ दिया अब तक इस टूर्नामेंट में दिल्ली की टीम ने 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम को 7 मैचों में जीत मिली है. जबकि चेन्नई ने 8 मैचों में से छह मुकाबलों में जीत हासिल की है और वह दूसरे पायदान पर है.

दिल्ली से मिली हार के बाद अब सनराइजर्स हैदराबाद के लिए प्लेऑफ में जगह बनाने के रास्ते खत्म होते नजर आ रहे हैं. हैदराबाद की टीम अब तक 8 में से केवल एक ही मुकाबला जीत पाई है और अंकतालिका में सबसे निचले पायदान पर चल रही है. तीसरे पायदान पर विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है, जिसने आठ में से पांच मैच जीते हैं.

वहीं चौथे नंबर पर चार जीत के साथ मुंबई इंडियंस बनी हुई है. जबकि पांचवें स्थान पर राजस्थान रॉयल्स है. कोलकाता नाइट राइडर्स छठे पायदान पर पहुंच गई है, जिसने 8 में से 3 मैच जीते हैं. लेकिन पंजाब किंग्स की हालत भी कुछ खास नहीं है. पंजाबी किंग्स ने 8 में स केवल तीन ही मैच जीते हैं और उसका नेट रन रेट भी माइनस में है. पंजाब को प्लेऑफ में जगह बनानी है तो उसे हर मुकाबले में जीत हासिल करनी होगी.

टीम	मैच	जीते	हारे	ड्रॉ	रनरेट	अंक
दिल्ली कैपिटल्स	9	7	2	0	+0.613	14
चेन्नई सुपरकिंग्स	8	6	2	0	+1.223	12
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर	8	5	3	0	-0.706	10
मुंबई इंडियंस	8	4	4	0	-0.071	8
राजस्थान रॉयल्स	8	4	4	0	-0.154	8
कोलकाता नाइटराइडर्स	8	3	5	0	+0.110	6
पंजाब किंग्स	9	3	6	0	-0.345	6
सनराइजर्स हैदराबाद	8	1	7	0	-0.689	2

Point Table - 2021

डूरंड कपः आर्मी रेड और एफसी बेंगलुरु यूनिइटेड का क्वार्टरफाइल मैच कोविड के चलते रद्द

कोलकाता (एजेंसी)।

आर्मी रेड और एफसी बेंगलुरु यूनिइटेड (एफसीबयू) के बीच शुक्रवार को कल्याणी स्टेडियम में खेला जाने वाला डूरंड कप का क्वार्टरफाइल मैच आर्मी रेड के एक खिलाड़ी के कोविड-19 पॉजिटिव होने के चलते रद्द कर दिया गया है।

गुरुवार को सभी खिलाड़ियों ने साथ में अभ्यास किया था जिसमें कोरोना के चपेट में आया हुआ खिलाड़ी भी शामिल था। आर्मी रेड की टीम ने टूर्नामेंट से बाहर होने का फैसला किया जिसके परिणाम स्वरुप बाई के तौर पर एफसीबयू को सेमीफाइनल में जगह मिल गई। यह समझा जा रहा है कि सुबह में निर्धारित टेस्ट के दौरान आर्मी रेड का खिलाड़ी पॉजिटिव पाया गया। आयोजन समीति ने बाकी के मैचों को कराने का फैसला किया है क्योंकि वह अलग स्थल पर होगा। इस बीच, एलओसी ने कोलकाता में भारी बारिश के कारण एफसी गोवा और दिल्ली एफसी के बीच क्वार्टर फाइनल मैच को मोहन बागान मैदान से कल्याणी स्टेडियम में स्थानांतरित करने का भी फैसला किया है।

हम मंधाना की रन बनाने की क्षमता का समर्थन करते हैं : दास

मकाय। भारतीय महिला टीम के बल्लेबाजी कोच शिव सुंदर दास ने ओपनर स्मृति मंधाना का समर्थन करते हुए कहा है कि वह जल्द ही रन बनाएंगी। स्मृति ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में 16 रन बनाए थे। मुकाबले में टीम को नौ विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। दास ने वर्चुअल प्रेस वार्ता में कहा, मैंने मंधाना के साथ चर्चा की है और अगले दो सत्र में हमने नेट्स पर काफी मेहनत की है। हमने कुछ दिक्कतों को देखा है। वह विश्व स्तरीय खिलाड़ी है और हम उनकी रन बनाने की क्षमता का समर्थन करते हैं। हम कल के मुकाबले में बदलाव देखेंगे। दास को भरोसा है कि मंधाना और शैफाली वर्मा दूसरे वनडे में बल्ले से टीम को अच्छी शुरूआत दिलाएंगी। उन्होंने कहा, मैंने खिलाड़ियों से बात की है और नेट्स पर हमने कुछ चीजें करने की कोशिश की है। हमारे पास मंधाना और शैफाली हैं जो पारी की शुरूआत करेंगी। हमारी कोशिश अच्छी शुरूआत करने की होगी। बल्लेबाजी कोच के रूप में मुझे भरोसा है कि वे टीम को मजबूत शुरूआत दिलाएंगी।

ऑस्ट्रेलिया की सलामी बल्लेबाज रेचल हेंस को नेट्स के दौरान लगी कोहनी में चोट

मकाय। भारत के खिलाफ दूसरे वनडे से एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया की सलामी बल्लेबाज रेचल हेंस को नेट्स के दौरान कोहनी में चोट लगी है। ऑस्ट्रेलिया की लगातार 25वीं वनडे जीत में नाबाद 93 बनाने वाली उपकप्तान हेंस को काफी तेजी से गेंद लगी थी और उन्हें तुरंत स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया। ऑस्ट्रेलिया के लगातार जीत के रिकॉर्ड सिलसिले में हेंस निरंतर टीम का हिस्सा रहीं हैं और 2017 विश्व कप के बाद से उन्होंने एक भी मुकाबला मिस नहीं किया हैं। अगर हेंस शुक्रवार के मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहती तो ऑस्ट्रेलिया के पास एलिसा हेली के साथ बेथ मूनी से ओपनिंग करवाने का विकल्प है। अन्यथा जॉर्जिया रेडमेन को भी डेब्यू मिल सकता है। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को कई चोटग्रस्त खिलाड़ियों को संभालना पड़ रहा है। पहले मुकाबले से पहले जेस जोनासन और टायला व्लेमिंक दोनों चोटिल होकर बाहर तो थीं ही, साथ में ऑलराउंडर निकोला कैरी भी दर्द के चलते पहले वनडे में नहीं खेल पाईं थीं। हालांकि, मुख्य कोच मैथ्यू मॉट और कप्तान मेग लेनिंग के अनुसार इससे अगले वर्ष होने वाले विश्व कप से पहले टीम की गहराई नापने का सुनहरा मौका मिला है। मंगलवार के पहले मुकाबले में डार्सी ब्राउन और डेब्यू कर रहीं हैन्ना डालिंगटन ने मिलकर छह विकेट लिए और जीत की नींव रखी। आगे के मैचों में स्टेला कैंपबेल और मेटलन ब्राउन जैसे तेज गेंदबाजों का पदार्पण भी देखने को मिल सकता है।

आईसीसी ने टी20 विश्व कप के लिए लॉन्च किया एंथम

दुबई (एजेंसी)।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने गुरुवार को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए अधिकारिक एंथम लॉन्च किया जिस कैपेन फिल्म में भारतीय कप्तान विराट कोहली और वेस्टइंडीज के कप्तान कीरोन पोलार्ड को एक नए अवतार में देखा गया।

आईसीसी टी20 विश्व कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक यूएई और ओमान में खेला जाएगा। एंथम को भारत के जाने माने संगीत निर्देशक अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया है।

कोहली और पोलार्ड के अलावा अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाज राशिद खान और ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल भी एंथम में एक अलग अवतार के रुप में नजर आएंगें। आईसीसी के हवाले से पोलार्ड ने कहा, टी20 क्रिकेट ने यह साबित किया है कि वह लगातार अपने फैंस को आकर्षित करने के लिए कुछ नया करता रहता है। पूरी दुनिया भर में जितने भी लोग इस टूर्नामेंट को देखेंगे, मैं दुबई में उनका मनोरंजन करने के लिए काफी उत्साहित हूं। मैक्सवेल ने कहा, आईसीसी टी20 विश्व कप काफी कठिन और मजेदार होने वाला है। कई टीमें हैं जो इस ट्रॉफी की हकदार हैं। हर मैच फाइनल की तरह होगा। हम जल्द से जल्द इसकी शुरुआत करना चाहते हैं।

सेरी ए : जुवेंतस ने हासिल की अपनी पहली जीत

रोम। जुवेंतस ने सेरी ए के मुकाबले में स्पेजिया को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट के इस सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज की।

जुवेंतस की ओर से मोएसे कियान ने 28वें मिनट में गोल कर टीम को शुरूआती बढ़त दिलाई। हालांकि स्पेजिया की ओर से इमेनुअल ग्यासी ने 33वें मिनट में गोल कर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। पहले हॉफ के खत्म होने तक दोनों टीमों के बीच मुकाबला 1-1 की बराबरी पर रहा। इसके बाद दूसरे हॉफ की शुरूआत में स्पेजिया की ओर से जेनिस एनतिस्ते ने 49वें मिनट में गोल कर स्कोर 2-1 किया। जुवेंतस ने भी वापसी करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया और फेडेरिको चिएसा ने 66वें मिनट में गोल कर स्कोर 2-2 से बराबर किया। इसके बाद जुवेंतस की ओर से मैथिस डी लाइट ने 72वें मिनट में गोल कर स्कोर 3-2 किया। फिर जुवेंतस ने जहां इस बढ़त को कायम रखने की कोशिश की तो वहीं स्पेजिया ने बराबरी हासिल करनी चाही। निर्धारित समय तक स्पेजिया बराबरी या बढ़त हासिल नहीं कर सका और उसे 36 बार की चैंपियन टीम के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।

नटराजन के कोरोना पॉजिटिव आने पर बोले बीसीसीआई अधिकारी, चिंतित लेकिन घबराने की जरूरत नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)।

आईपीएल के दूसरे चरण में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है और सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज टी. नटराजन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बुधवार को हुए मैच से पहले कोरोना संक्रमित पाए गए थे।

क्रिकेटर यहां कड़े बायो बबल में हैं और सभी तरह के एहतियात बरत रहे हैं। आईपीएल में कोरोना का मामला सामने आने से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) चिंतित है। बीसीसीआई के सीनियर अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, नहीं पता यह कैसे हुआ। खिलाड़ी यहां कड़े बायो बबल में हैं और हमने उन्हें अब ज्यादा एहतियात बरतने के लिए कहा है। हम उम्मीद करते हैं कि और कोई मामले सामने नहीं आएं जिससे टूर्नामेंट प्रभावित हो। हम चिंतित हैं लेकिन फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छे की उम्मीद करते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या स्टेडियम के अंदर दर्शकों को शामिल होने की मंजूरी देना सही फैसला था। अधिकारी ने कहा, सनराइजर्स हैदराबाद ने बुधवार को अपना पहला मैच खेला और नटराजन इससे पहले पॉजिटिव पाए गए। पूरी टीम कड़े बबल में थी। नटराजन के साथ ही उनके करीब में आए छह करीबी लोगों को आईसोलेट किया गया। हालांकि, अन्य खिलाड़ियों के टेस्ट नेगेटिव आने पर बीसीसीआई ने मैच का कराने

का फैसला किया। इससे पहले, मई में बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजों में कोरोना के मामले सामने आने के बाद आईपीएल 2021 को स्थगित कर दिया था। चर्चा करने के बाद बोर्ड ने शेष मुकाबलों को यूएई में कराने का फैसला किया था।

मुझे लगता है कि खिलाड़ियों और संगठनों के लिए पाकिस्तान को ना कहना आसान है : ख्वाजा

नई दिल्ली (एजेंसी)।

ब्रिस्बेन, 23 सितम्बर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का मानना है कि खिलाड़ियों और टीमों के लिए पाकिस्तान दौरे को ना कहना बहुत आसान है। उनका यह भी मानना है कि अगर भारत के साथ ऐसा होता तो परिदृश्य अलग होते।

पिछले शुक्रवार को न्यूजीलैंड ने पहला वनडे शुरू होने के कुछ देर पहले ही सुरक्षा कारणों का हवाला देकर दौरा रद्द कर दिया था। इसके बाद सोमवार को इंग्लैंड ने अक्टूबर-नवंबर में पुरुष और महिला टीमों के पाकिस्तान दौरे को भी रद्द कर दिया।

ख्वाजा ने कहा, मुझे लगता है कि खिलाड़ियों और संगठनों के लिए पाकिस्तान को ना कहना बहुत आसान है, क्योंकि यह पाकिस्तान है। मुझे लगता है कि अगर बांग्लादेश होता तो भी यही बात लागू होती। लेकिन कोई भी भारत को ना नहीं कहेगा, अगर वे इसी स्थिति में हों। उन्होंने कहा, पैसा बोलता है, हम सभी जानते हैं और यह शायद इसका एक बड़ा हिस्सा है। वे अपने

टूर्नामेंट के माध्यम से बार-बार साबित करते रहते हैं कि क्रिकेट खेलने के लिए यह एक सुरक्षित जगह है। मुझे लगता है कि कोई कारण नहीं है कि हमें वापस नहीं जाना चाहिए।

ख्वाजा ने कहा, बहुत सुरक्षा है। भारी सुरक्षा। मैंने लोगों के सुरक्षित महसूस करने के बारे में रिपोर्ट के अलावा कुछ नहीं सुना है। ख्वाजा का जन्म पाकिस्तान की राजधानी इस्लमाबाद में हुआ था और वह पांच साल की उम्र में सिडनी चले गए थे। उन्होंने अगस्त 2019 में इंग्लैंड में एशेज सीरीज के बाद टेस्ट मैच नहीं खेला है।

हमें अपने क्रिकेट में सुधार करना होगा : विलियमसन

दुबई। सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) की इंडियन प्रीमियर लीग 2021 (आईपीएल) के दूसरे चरण की शुरुआत बेहद खराब रही उन्हें बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) से आठ विकट से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद एसआरएच के कप्तान केन विलियमसन ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि हमें अपने खेल में सुधार करने की जरुरत है। हमारी शुरुआत बेहद खराब रही और अपने आने वाले मैचों पर ध्यान देना चाहिए। एसअरएच की टीम सात मैचों में एक जीत के साथ अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर थी। डीसी के खिलाफ एसआरएच ने पहले बल्लेबाजी की पर उनकी शुरुआत बेहद खराब रही। सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर पहले ओवर के तीसरे गेंद पर ही आउट हो गए। टीम उसके बाद से उबर नहीं पाई पर फिर भी उन्होंने 20 ओवर में 9 विकेट 134 रन बनाए। कप्तान विलियमसन का मानना है कि उनकी टीम 25-30 रन और बना सकती थी। मैच के बाद विलियमसन ने कहा, हमने जो सोचा था वैसी शुरुआत हमें नहीं मिली हमारे स्कोर में 25-30 की कमी थी। यह शर्मनाक है पर हमें अपने मनोबल को उचां रखना है। यह टूर्नामेंट हमारे लिए काफी कठिन रहा है। एसआरएच ने अभी तक इस टूर्नामेंट के आठ मौचों में सिर्फ एक जीत हासिल की है। कप्तान विलियमसन का मानना है कि वह अपने अच्छे दिन पर किसी को भी मात दे सकते हैं। विलियमसन ने कहा, हम अपने अच्छे दिन किसी भी टीम को हरा सकते हैं। दिल्ली की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, उन्होंने हमें दबाव में डाला और इसकी आप अपेक्षा भी रखते हैं। अब हमें यहां से अपने खेल पर ध्यान देना होगा और अपने क्रिकेट में सुधार करना होगा।

पैरालंपिक कांस्य पदक विजेता शरद को हार्ट इनफ्लेमेशन, कुछ और परीक्षण के नतीजों का इंतजार

नई दिल्ली (एजेंसी)।

नयी दिल्ली।तोक्यो पैरालंपिक कांस्य पदक विजेता ऊंची कूद के एथलीट शरद कुमार 'हार्ट इनफ्लेमेशन' (सीने में जलन) से पीड़ित हैं और उन्होंने कुछ और परीक्षण कराये हैं जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। कुमार ने 31 अगस्त को तोक्यो पैरालंपिक में टी-42 ऊंची कूद स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। उन्हें पिछले हफ्ते सीने में जकड़न की शिकायत के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया। कुमार ने गुरूवार को कहा, ''शुरूआती रिपोर्ट में पता चला है कि मेरे दिल की मांसपेशियों में सूजन है।'' पटना में जन्में 29 साल के कुमार छतरपुर में रहते हैं।

कुमार को इस हफ्ते के शुरू में अस्पताल से छुट्टी मिल गयी लेकिन उन्हें कुछ और जांच के लिये वापस आना पड़ा। उन्होंने कहा, ''मैं यहां कुछ और जांच के लिये वापस आया हूं। मैं सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर रहता हूं, मैंने अस्पताल के अधिकारियों से कहा कि मुझे घर जाने दें।'' कुमार को बचपन में पोलियो की गलत दवाई देने के कारण बायें पैर में लकवा मार गया था। उन्होंने पिछले महीने तोक्यो में टी-42 फाइनल में हिस्सा लिया था जबकि अपनी स्पर्धा से पहले ट्रेनिंग के दौरान उनके घुटने में चोट लग गयी थी। बाद में उन्होंने खुलासा किया था कि चोट के कारण वह प्रतियोगिता से हटने का विचार कर रहे थे। लेकिन उन्होंने 1.83 मीटर की कूद लगाकर कांस्य पदक जीता था।